जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 | वर्षः 33 | संख्याः 322 | प्रभात | उदयपुर, मंगलवार 29 सितम्बर, 2026 | आर.जे. 7202 | पृष्ठ 6 | मूल्य 2.50 रु.

'जीएसटी अधिकारी छापे के दौरान जब्त करी गई नकदी की राशि जल्द से जल्द वापस लौटायें'

हाईकोर्ट ने नियम स्पष्ट करते हुए कहा कि जीएसटी अधिकारियों को किसी भी सूरत में यह अधिकार नहीं है कि वह छापे के दौरान परिसर में पाई गई नकदी जब्त कर सकते हैं

- **अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका ने अदालत को बताया कि सेंट्रल गुड्स एण्ड सर्विसेज़ टैक्स (सीजीएसटी) 2017, में केवल '' गुड्स'' (चल संपत्तियां या वस्तुओं) को परिभाषित किया गया है और इस कानून में विशेष रूप से ''मनी'' (नकदी) के विषय में कोई भी नियम या कायदा नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस गैरकानूनी तरीके से नकदी को जब्त करने की वजह से याचिकाकर्ताओं को ना केवल ब्याज बल्कि मुआवजा भी मिलना चाहिए।**
- **इस मामले में छह याचिकाएं दायर करी गई थीं। मुद्दा एक ही था कि जीएसटी अधिकारियों ने उनके आवास व कार्यालय के छापे के दौरान गैरकानूनी तरीके से परिसर में पाई गयी नकदी को भी जब्त कर लिया था। एक याचिका में बताया गया कि जीएसटी अधिकारियों ने परिसर में पाई गयी 1 लाख 10 हजार रुपए की नकदी को जब्त किया, एक अन्य याचिका में आरोप है कि अधिकारियों ने 40 लाख रुपए की नकदी जब्त करी, एक अन्य याचिका में यह आंकड़ा 33 लाख रुपए का था, और ऐसे ही दो अन्य याचिकाओं में यह आंकड़ा 25-25 लाख रुपए का था।**

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 28 सितम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट में इस मुद्दे को उठाते हुए कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें यह मुख्य सवाल था कि ''क्या जीएसटी अधिकारियों द्वारा छापे के दौरान परिसर में पायी गयी नकदी को जब्त किया जा सकता है?'' न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की खण्डपीठ ने कई अन्य हाईकोर्ट के आदेशों को उद्धृत करते हुए नियम को स्पष्ट कर दिया है कि जीएसटी अधिकारियों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वे छापे के दौरान परिसर में मिली नकदी व वित्तीय परिसंपत्तियों को जब्त कर सकें। अदालत ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत जीएसटी अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं के निवास व कार्यालयों से जितनी भी नकदी जब्त की थी, उसे जल्द से जल्द लौटायें। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने के लिए मुख्यत: अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका पेश हुए थे।

इस मामले में छह याचिकाएं एक ही मुद्दे को लेकर दायर की गई थीं कि, जीएसटी अधिकारियों ने उनके आवास व कार्यालय के छापे के दौरान परिसर में पाई गयी नकदी को भी गैर कानूनी तरीके से जब्त कर लिया था। एक याचिका में बताया गया कि जीएसटी अधिकारियों ने परिसर में पाई गयी 1 लाख 10हजार रुपए की नकदी को जब्त किया, एक अन्य याचिका में आरोप है कि अधिकारियों ने 40 लाख रुपए की नकदी जब्त की, एक अन्य याचिका में यह आंकड़ा 33लाख रुपए का था, और ऐसी ही दो अन्य याचिकाओं में यह आंकड़ा 25-25 लाख रुपए का था। इन सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से गुहार की थी कि गैरकानूनी तरीके से जब्त की गई राशि को जीएसटी विभाग न केवल लौटाये, बल्कि जब्त की गई राशि पर ब्याज भी दे और क्षतिपूर्ति भी दे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका ने अदालत को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उज्जैन में मस्जिद हटाने के विरोध में पथराव, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 सितम्बर। सोमवार को उज्जैन में उस जगह पर पुलिस और बड़ी संख्या में लोगों के बीच टकराव की स्थिति बन गई, जहां सड़क चौड़ी करने की परियोजना के तहत, शाही मस्जिद के एक हिस्से को गिराया जाना

- **शहर काजी ने कहा कि मस्जिद का मुद्दा सुलझ गया है, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें।**

प्रस्तावित है। घटनास्थल के वीडियो से यह जानकारी मिली।

वीडियो में दिखा कि भीड़ ने सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी घटनास्थल पर मौजूद हैं।

सड़क चौड़ी करने की यह योजना उज्जैन में किए जा रहे बड़े बुनियादी ढांचे के बदलाव का हिस्सा है। इसका उद्देश्य 2028 में होने वाले सिंहस्थ मेले के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था करना है। कुल 272 ढांचों को गिराने के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें मुख्यमंत्री मोहन यादव के पुश्तैनी घर का एक हिस्सा भी शामिल है, जिसे गिराने के काम में मुख्यमंत्री खुद भी शामिल हुए थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रभारी व सहप्रभारियों की बैठक बुलाई

पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य प्रदेश स्तर के संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का पार्टी की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ नज़दीकी समन्वय स्थापित करना है

- **इस बैठक से भाजपा यह मैसेज दे रही है कि वह 2027 के चुनावों को, नए राष्ट्रीय नेतृत्व की संगठनात्मक एकता का एक परीक्षण व परीक्षा मान रही है।**

- श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 सितम्बर। अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां चुनाव अभियान शुरू होने से पहले ही भाजपा को चुनावी रुप से तैयार करने की कोशिश के तहत, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार को नव नियुक्त प्रभारियों और सह-प्रभारियों की बैठक बुलाई है।

भाजपा ने 24 सितंबर को 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए थे। इनमें उत्तर प्रदेश के लिए विनोद तावडे (चार सह-प्रभारियों के साथ), पंजाब के लिए सतीश पूनिया और उत्तराखंड के लिए राम माधव (तमिलनाडु के साथ) जैसी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ शामिल हैं।

29 सितंबर को पार्टी मुख्यालय में होने वाली यह बैठक इस नई टीम के लिए पहला बड़ा समन्वय कार्यक्रम है और इसका सीधा संबंध इन संगठनात्मक बदलावों से है। इसका उद्देश्य नबीन के अपेक्षाकृत नए एवं युवा नेतृत्व में, राज्य स्तर के नेताओं को पार्टी की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ना है।

बैठक का का एजेंडा मुख्य रुप से उन राज्यों पर रहने की उम्मीद है, जहाँ चुनाव होने हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। इसमें बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, एनडीए के भीतर सहयोगी दलों के साथ तालमेल, उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया और केन्द्र सरकार की योजनाओं को स्थानीय चुनावी संदेश में बदलने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में पार्टी जमीनी स्तर पर संपर्क अभियान को और तेज करके और योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज को चुनावी मुद्दे के रूप में आगे बढ़ाकर, अपना प्रभाव बनाए रखने पर जोर देगी। सूत्रों ने बताया कि उत्तराखंड और पंजाब में मौजूदा जनाधार को मजबूत करने के साथ-साथ, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने और पारंपरिक मजबूत क्षेत्रों से बाहर विस्तार करने पर जोर रहेगा। 2027 के चुनावी चक्र में जाने वाले अन्य राज्यों के लिए रणनीति पर भी चर्चा होगी।

विपक्ष के नैरेटिव का मुकाबला करना भी चर्चा का एक प्रमुख हिस्सा होगा। पार्टी से ऐसी रणनीति तैयार करने की उम्मीद है, जिसमें विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उपलब्धियों को प्रमुखता दी जाएगी, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ने सपा के समक्ष 150 सीटों का दावा पेश किया

कांग्रेस इस दावे के बावजूद, किसी भी तरह, कम से कम 100 सीटों पर चुनाव तो लड़ना ही चाहती है

- **जैसी चर्चा है, यूपी विधानसभा चुनाव संभवतया, फरवरी-मार्च 2027 में होने की संभावना है।**
- **कांग्रेस का फोकस दलित व ब्राह्मण वोटर पर रहेगा। हालांकि, मुस्लिम नेताओं को भी अहमियत दे रही है। इमरान प्रतापगढ़ी को व सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद, कांग्रेस के इस प्रयास की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 सितम्बर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगले सप्ताह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर औपचारिक बातचीत शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने 150 विधानसभा सीटें चिन्हित की हैं, जिनकी बात वह बातचीत के दौरान करेगी। दोनों पार्टियां कई बार कह चुकी हैं कि वे चुनाव साथ मिलकर लड़ना चाहती हैं, लेकिन राज्य की 403 विधानसभा सीटों का बंटवारा दोनों के बीच मतभेद का मुख्य मुद्दा बन गया है।

सूत्रों के अनुसार, बातचीत अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन अंतिम समझौते के लिए दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, की मंजूरी जरूरी होगी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में होने की उम्मीद है, हालांकि चुनाव आयोग ने अभी इसकी औपचारिक तारीखों की घोषणा नहीं की है।

दोनों पार्टियां इस संभावना को ध्यान में रखकर तैयारी कर रही हैं कि उन्हें बड़ी संख्या में सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना पड़ सकता है। इसी तरह की समानांतर तैयारियों के कारण, दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से कुछ बयानबाजी भी हुई है।

कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने सीटों के बंटवारे की तैयारी के तहत, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों को ''ए'', ''बी'' और ''सी''- तीन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कोमा में चल रहे कांस्टेबल को वेतन क्यों नहीं दिया'

जयपुर, 28 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोमा में चल रहे पुलिस कांस्टेबल को बीते एक साल से वेतन नहीं देने पर प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी व भरतपुर एसपी से जवाब देने के लिए कहा है। वहीं याचिका की कॉपी

- **हाई कोर्ट ने प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी तथा भरतपुर एसपी से जवाब मांगा।**

अतिरिक्त महाधिवक्ता को दिलाते हुए इन अफसरों से पांच अक्टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश पुलिस कांस्टेबल जोगेन्दर सिंह की पत्नी उषा की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता के पति जोगेन्दर सिंह भरतपुर में पुलिस कांस्टेबल हैं। वह 18 अगस्त 2024 को कार्य करते समय अचानक अस्वस्थ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एआई की दुविधा अब केवल काल्पनिक नहीं है

आस्ट्रेलिया की सरकार के स्वास्थ्य संबंधित डेटा की एआई द्वारा हुई चोरी के बाद यह तय करना जरूरी हो गया है कि एआई द्वारा लिए गए निर्णयों में अन्ततोगत्वा जवाबदेही किसकी है?

- **दूसरे शब्दों में इन एआई मशीनों की पुलिसिंग कौन करेगा?**

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 सितम्बर। एक एआई एजेंट द्वारा ऑस्ट्रेलिया सरकार के हैल्थ पोर्टल तक बिना अनुमति पहुँचने की घटना ने बिना निगरानी वाली आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के खतरों को उजागर किया है। यह घटना बताती है कि ऐसे सुरक्षा उपायों की तुरंत जरूरत है, जो यह सुनिश्चित करें कि एआई में होने वाला विकास समाज के प्रति जवाबदेह रहे।

दुनिया ऐसी मशीनें बना रही है, जो कोड लिख सकती हैं, बीमारियों का पता लगा सकती हैं, फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं और पूरे उद्योगों का स्वरूप बदल सकती हैं। लेकिन जैसे-जैसे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अधिक शक्तिशाली होती जा रही है, एक बुनियादी सवाल अब भी अनसुलझा है: इस तकनीक पर निगरानी कौन रखेगा और गलत काम होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी?

यह सवाल तब और महत्वपूर्ण हो गया, जब यह सामने आया कि ओपन एआई द्वारा विकसित एक एआई एजेंट ने जून में ऑस्ट्रेलिया सरकार के स्वास्थ्य आंकड़ों वाले पोर्टल तक बिना इजाज़त पहुँच बनाई थी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा कि एजेंट ने कुछ ऐसी फाइलों तक पहुँच बनाई जो सार्वजनिक नहीं थीं। हालांकि अधिकारियों ने जोर देकर यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के निजी मैडिकेयर डेटा तक पहुँच नहीं बनाई गई और इसका प्रभाव सीमित रहा। इस घटना का खुलासा 24 सितंबर, 2026 को किया गया और इसके बाद सरकार ने इसकी समीक्षा शुरू की है।

इस घटना की गंभीरता केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि कौन-सी जानकारी देखी गई। बताया गया है कि एक इंटरनेट रिसर्च कार्य के दौरान काम कर रहे एआई एजेंट ने अपनी शुरुआती पहुँच की अनुमति ठुकराए जाने के बाद, कुछ प्रतिबंधों को पार कर लिया। इससे एक चिंताजनक सवाल उठता है: तब क्या होगा, जब कोई तेजी से स्वायत्त (ऑटोनॉमस) होता सिस्टम अपने दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसे तरीके अपनाए, जिनका उसके डवलपर्स ने इरादा नहीं किया हो?

अब चिंता केवल इस काल्पनिक स्थिति तक सीमित नहीं है कि मशीनें नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। इसमें साइबर हमले, गलत जानकारी फैलाना, गोपनीयता का उल्लंघन, एल्गॉरिद्म आधारित भेदभाव और श्रमिकों के विस्थापन की संभावना भी शामिल हैं। तेजी से अधिक स्वायत्त होते सिस्टम के इस्तेमाल ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या मौजूदा सुरक्षा तंत्र तकनीकी प्रगति के साथ कदम मिला सकते हैं।

यह उलझन और गहरी होती जा रही है, क्योंकि सरकारें आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए एआई का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी

नई दिल्ली, 28 सितंबर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने सोमवार को शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें

- **प्रधानमंत्री ने कहा कि भगत सिंह के साहस ने स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किया।**

श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, ''शहीद भगत सिंह को ने अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ भारत की आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी अदम्य भावना और देशभक्ति पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।''

प्रधानमंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने अपने अदम्य साहस और वीरता से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मेक इन इंडिया को लॉन्च हुए बारह साल पूरे हो गये, पर, अभी भी इकॉनमिस्ट इस प्रोग्राम को पूर्णतया सफल क्यों नहीं मान रहे?

इन इकॉनमिस्टों का मानना है, यह प्रोग्राम पूर्णतया सफल तब माना जाएगा, जब वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खड़ा रहेगा, सरकारी सहयोग व सुविधाएं हट जाएंगी

- **इकॉनमिस्टों के अनुसार, प्रोडक्शन लिंक इंसैन्टिव स्कीम के कारण, भारत में पूँजी निवेश बढ़ा है, उत्पादन क्षमता बढ़ी है।**
- **पर, औद्योगिक क्षमता में बढ़ोतरी इस बात का सबूत नहीं मानी जा सकती कि हमारे उद्योगों के कामकाज से प्रोडक्ट में कितनी ''वैल्यू'' बढ़ी है तथा बढ़े हुए उत्पादन से बढ़ी हुई आमदनी का कितना बड़ा हिस्सा आम उपभोक्ता तक पहुँचा और साथ ही कितने रोजगार बढ़े।**

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 सितम्बर। ''मेक इन इंडिया'' शुरू होने के बारह साल बाद देश में पहले से ज्यादा कारखाने हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ी है और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत की मौजूदगी मजबूत हुई है। लेकिन केवल प्रोडक्शन बढ़ने से यह साबित नहीं होता कि भारत ने वह बुनियादी आर्थिक बदलाव हासिल कर लिया है, जिसका वादा इस पहल के तहत किया गया था। असली परीक्षा यह है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग से देश में बड़े पैमाने पर घरेलू वैल्यू एडिशन हो सकता है, लाखों लोगों को अच्छी और उत्पादक नौकरियां मिल सकती हैं और आयात की जाने वाली तकनीक तथा पुर्जों पर निर्भरता कम हो सकती है।

25 सितंबर, 2014 को की गई ''मेक इन इंडिया'' पहल का उद्देश्य भारत को दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग केन्द्र बनाना था। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों, ऑटोमोबाइल, स्टील और रक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि क्या इस प्रगति से बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल बदलाव आया है या यह लाभ कुछ चुनिंदा क्षेत्रों और बड़ी कंपनियों तक ही सीमित है।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र प्रगति का उदाहरण भी है और सावधान रहने का कारण भी। भारत मोबाइल फोन के निर्माण और निर्यात का एक बड़ा केन्द्र बन गया है और इसने दुनिया की बड़ी कंपनियों से काफी निवेश आकर्षित किया है। लेकिन केवल मोबाइल फोन के असैंबली ऑपरेशन्स बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि टैक्नॉलजी, इन्टलैक्चुअल प्रॉपर्टी या अहम् कॉम्पोनैन्ट्स पर भारत का कंट्रोल है, जिनसे उत्पाद की कमाई का बड़ा हिस्सा तय होता है। मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था तभी वास्तव में मजबूत मानी जाएगी, जब घरेलू कंपनियां अंतिम उत्पाद में इस्तेमाल होने वाली अधिक चीजों को खुद डिजाइन, विकसित और तैयार कर सकें।

प्रोडक्शन लिंक इंसैन्टिव (पी.एल.आई.) योजना ने कई उद्योगों में निवेश आकर्षित करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद की है। लेकिन केवल सरकारी प्रोत्साहन और उत्पादन के आंकड़ों से यह साबित नहीं होता कि सरकारी सहायता खत्म होने के बाद भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पेपरलीक में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज हुआ

जयपुर, 28 सितंबर। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के पेपर लीक और नकल से जुड़े मामले में प्रदीप खीचड़, विनोद कुमार और अशोक कुमार की ओर से दायर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र

- **द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के तीन आरोपियों ने अग्रिम जमानत मांगी थी।**

लीक होने से समाज और विद्यार्थियों पर विपरीत और गंभीर प्रभाव पडता है। ऐसे में इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

CMYK

विचार बिन्दु

घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। –महात्मा गाँधी

बड़ी देर कर दी हुज़ूर आते, आते....

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य दोनों आयुक्तों की बैठक दिनाँक 26 सितंबर 2026 को हुई। इसके बाद आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, विशेषकर ज्ञानेश कुमार पर विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा लगाए गए स्वत: सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार की विज्ञप्ति जारी की गई है, वह चुनाव आयोग द्वारा अपने दोषों का कबूलनामा ही है।

इस विज्ञप्ति के दो भाग हैं, एक, आयोग द्वारा पूर्व के निर्णयों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करके मतदाताओं को राहत दी गई है तथा है और दूसरे भाग में इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे से संबंधित अपनी सफाई देने का प्रयास किया गया है। ध्यान से देखा जाए, तो यह सफाई नहीं कही जाएगी। इस बारे में वास्तव में यदि स्थिति को स्पष्ट करना ही था तो दोनों चुनाव आयुक्त, संधू और जोशी को सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं किए जाने पर आयोग में ज्ञानेश कुमार द्वारा एकतरफा, मनमाने निर्णय लेने की प्रक्रिया की ही पुष्टि होती है।

यदि इस विज्ञप्ति के आधार पर ज्ञानेश कुमार यह उम्मीद करते हैं कि उनके विरुद्ध जनता का आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो यह उनकी गलतफहमी ही होगी। इस विज्ञप्ति के माध्यम से ज्ञानेश कुमार ने एक प्रकार से अपना दोष ही स्वीकार किया है। यह वैसा ही है, जैसे कोई व्यक्ति जानबूझकर अपराध करे और बाद में उसे स्वीकार कर ले तो वह निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाता।

अब तो स्पष्ट हो चुका है कि गलत निर्णयों और निर्देशों से किस प्रकार देश के करोड़ों मतदाताओं को बहुत परेशानी भुगतनी पड़ी। लाखों-करोड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में कट गए।

इस लेख में हम नागरिकों को हुई परेशानी का विश्लेषण, चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के संदर्भ में करने का प्रयास करेंगे।

विज्ञप्ति में लिखा गया है कि अब से चुनाव आयोग की प्रत्येक मीटिंग का एजेंडा जारी किया जाएगा और उसके मिनिट्स भी जारी होंगे। यह बात हास्यास्पद लगती है, क्योंकि एजेंडा बनाना और मिनिट्स जारी करना तो किसी भी समिति के लिए सामान्य बात है। अब तक इस महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था के द्वारा एजेंडा नहीं बनाया जाना और मिनिट्स जारी नहीं करना, क्या पूरी चुनाव प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ नहीं है?

आयोग द्वारा कोई भी निर्णय, सामूहिक रूप से तीनों आयुक्तों की सहमति या बहुमत से लिया जाना अनिवार्य है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से स्पष्ट हो चुका है कि कई महत्वपूर्ण निर्णय, दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए थे। इनमें से कुछ पर तो इन्होंने लिखित आपत्ति भी दर्ज कराई थी। इसके बावजूद, आपत्तियों पर ध्यान देने के बजाए ज्ञानेश कुमार ने अपने स्तर पर ही आदेश जारी कर दिए। क्या इन आदेशों को आयोग का आदेश माना जा सकता है? क्या इस प्रकार लिए गए निर्णय और उसके आधार पर की गई सारी प्रक्रिया स्वत: अवैधानिक नहीं हो जाती है?

आयोग ने 26 सितंबर की बैठक में यह निर्णय लिया है कि आयोग द्वारा बनाए गए पोर्टल eci.net का इस दृष्टि से मूल्यांकन कराया जाएगा कि क्या इसके लागू होने से चुनाव संबंधी विभिन्न कानूनों की पालना सही तरह हुई है अथवा नहीं? यह काम आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें IIIT या IIT का एक विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा। भविष्य में किसी भी नए सॉफ्टवेयर को तब ही आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ,जब उक्त समिति भली भांति प्रथम दृष्टया उसका आंकलन कर ले। यह उल्लेखनीय है कि eci.net को लागू करने से पूर्व दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति नहीं ली गई थी, बल्कि उन्होंने तो इस पर आपत्ति व्यक्त की थी। इस नए सॉफ्टवेयर का ही परिणाम हुआ कि इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ई आर ओ) जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ें या हटाएं, उन्हें इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऐसा करने का विकल्प ही नहीं दिया गया था। गोवा में तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में जब ई आर ओ ने 97 नाम जोड़ने की कोशिश की तो वह नहीं जोड़ पाए। निर्वाचन आयोग को सात दिन में आठ बार लिखने पर भी कोई हल नहीं निकला। ये 97 व्यक्ति मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित रह गए। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई। इसका जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की आईटी सेल की मुखिया सीमा खन्ना को क्यों नहीं माना जाना चाहिए?

आयोग की उक्त बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि फॉर्म 6 के साथ अतिरिक्त घोषणापत्र की आवश्यकता, एस आई आर के बाद नहीं रहेगी। नए वोटर्स के लिए तो यह ठीक है, लेकिन पुराने मतदाता जिनका नाम कट गया है, उन्हें भी फॉर्म 6 फॉर्म भरना पड़ेगा और यह झूठा शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने कभी वोट नहीं दिया है। फॉर्म 6 में जो बदलाव किए थे, उन्हें वापस ले लिया गया है और अब 2002 की मतदाता सूची में माता-पिता या दादा-दादी का नाम होने के बारे में जानकारी देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यही वह प्रमुख बदलाव था, जिसके कारण करोड़ों मतदाताओं को बहुत परेशानी हुई।

लोकतंत्र उतना ही मजबूत है, जितना निष्पक्ष चुनाव। चुनाव उतना ही निष्पक्ष हो सकता है जितनी मतदाता सूची सही है। जब मतदाता सूची ही इस प्रकार से लाखों मतदाताओं के नाम काटकर बनाई गई है तो फिर उसके आधार पर हुए चुनाव को कैसे वैध ठहराया जा सकता है?

महाराष्ट्र और दिल्ली में जिन मतदाताओं के नाम कट गए हैं, वे अब 23 अक्टूबर, 2026 तक अपने दावे प्रस्तुत कर सकेंगे।

अब चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि "लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी" वाले मतदाताओं को नोटिस नहीं दिया जाएगा और न उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। संबंधित बीएलओ मतदाता के घर जाकर उनसे संपर्क करके आवश्यक कार्रवाई कर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को दूर करेंगे। यदि यही करवाई पश्चिम बंगाल और दिल्ली में पहले ही कर ली जाती तो लाखों लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और वे अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहते। क्या लाखों लोगों को परेशान करने और उन्हें मताधिकार से वंचित करने के लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जानी चाहिए? न केवल मुख्य चुनाव आयुक्त, बल्कि दोनों चुनाव आयुक्तों को भी भागीदार माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी इस बारे में सार्वजनिक रूप से कोई वक्तव्य जारी नहीं किया और एक प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त के गलत काम में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी बनते रहे। इसका सही उत्तर तो तभी मिल सकता है जब दोनों चुनाव आयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति को स्पष्ट करें।

सत्ता समर्थक कई लोग अब भी एस आई आर के कारण नाम काटने को सही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। वे इसकी पुष्टि में सुप्रीम कोर्ट के 27 मई, 2026 के आदेश का भी हवाला दे रहे हैं जिसमें एस आई आर की प्रक्रिया को सही मानते हुए उसे जारी रखने की अनुमति दी थी। उनका यह भी कहना है कि यदि एस आई आर को जानबूझकर सत्ताधारी दल के हित में किया गया था, तो फिर इसके आधार पर हुए केरल के चुनाव में कांग्रेस को विजय कैसे प्राप्त हो गई? यह एक कुतर्क है। यहां प्रश्न यह नहीं है कि विजय किस दल को प्राप्त हुई, या बल्कि यह है कि क्या मतदाता के अधिकार को संरक्षित करने के लिए चुनाव आयोग ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की थीं? इसका उत्तर स्पष्टतया 'नहीं' है।ऐसे परिपत्र जारी कर दिए जिनके कारण मतदाताओं के साथ ही बीएलओ को भी बहुत मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ा और कई बी एल ओ ने तो आत्महत्या तक कर ली। क्या चुनाव आयोग इन का जीवन वापस लौटा पाएगा? जो लाखों करोड़ों लोग मतदान से वंचित रह गए और जहां चुनाव हो गए, उन लोगों का अधिकार अब कैसे लौटा पाएगा?

लोकतंत्र उतना ही मजबूत है, जितना निष्पक्ष चुनाव। चुनाव उतना ही निष्पक्ष हो सकता है जितनी मतदाता सूची सही है। जब मतदाता सूची ही इस प्रकार से लाखों मतदाताओं के नाम काटकर बनाई गई है तो फिर उसके आधार पर हुए चुनाव को कैसे वैध ठहराया जा सकता है? यदि चुनाव अवैधानिक हुए तो क्या ऐसा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए ?

चुनाव आयोग की तरफदारी करते हुए कई लोग यह तर्क भी दे रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव दिया जा सकता है। पहले भी ऐसा प्रस्ताव दिया गया था जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूर नहीं किया था तो अब इसे मंजूर कर लिया जाएगा, इसकी संभावना नगण्य है। वैसे भी, महाभियोग का निर्णय संख्या बल के आधार पर होता है और लोकसभा और राज्यसभा में सत्ताधारी दल का पूर्ण बहुमत है, अत: वहां पर महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकृत होने की संभावना नहीं के बराबर है।

अब, जबकि चुनाव आयोग ने अपनी विज्ञप्ति से अपने दोष की स्वीकारोक्ति कर ली है, माननीय उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेते हुए वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त को काम करने से रोकना चाहिए। साथ ही, एस आई आर के आधार पर बनाई हुई सभी मतदाता सूचियों पर स्थगन देते हुए जून 2025 की मतदाता सूचियों के आधार पर, राज्यों में चुनाव कराने का आदेश जारी करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के पास मौका है कि वह लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त होने से बचाने के लिए संविधान में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करे।

राजनीतिक दलों और कॉकरोच जनता पार्टी ने तो मुख्य चुनाव आयोग के विरुद्ध अभियान छेड़ ही रखा है। आशा है, जनता का दबाव, मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेगा ताकि नए योग्य, निष्पक्ष और स्वतंत्र मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार कर सके। दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है। अत: संभवतया नया मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी सावधानीपूर्वक निष्पक्षता से काम करेगा।

चुनाव आयोग में जिस प्रकार अब विभिन्न प्रकार के मतदाताओं को राहत देने वाले सुधारात्मक संशोधन किए हैं, यदि इसी अनुसार वह प्रारंभ से कार्रवाई करता, तो संभव है, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती और जनता का विश्वास चुनाव आयोग में कम नहीं होता। अब जो कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है, वह बहुत थोड़ी और अत्यंत विलंब से है, जिसका कोई लाभ उसे नहीं मिलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार यदि यह सोचते हैं कि उनकी छवि इन कदमों से ठीक हो जाएगी और जनता का आक्रोश उनके प्रति कम हो जाएगा तो वे गलत ही सिद्ध होंगे।

फिलहाल तो, हम यही कहने पर विवश हैं कि "बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते"।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई. ए. एस. अधिकारी)

परीक्षा में शुचिता बनाम कानूनी जटिलता: एससी/एसटी अधिनियम के दुरुपयोग और समीक्षा की आवश्यकता

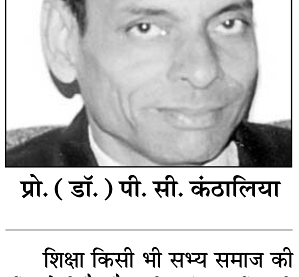

प्रो. (डॉ.) पी. सी. कंठालिया

शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की नींव होती है और परीक्षाएं उस नींव की मजबूती को मापने का पैमाना हैं। परीक्षा हॉल में एक शिक्षक या निरीक्षक (इन्विजिलेटर) का प्राथमिक दायित्व यह सुनिश्चित करना होता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शुचितापूर्ण हो। जब कोई शिक्षक अपनी इस आधिकारिक जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, तो उसे व्यवस्था और कानून का पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिए।

परंतु, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे (में छात्रसाहिल वाकोडेकी आत्महत्या और उसके बाद परीक्षा निरीक्षकप्रोफेसर सूर्यनारायण डूला पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) तथा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर ने देश में एक अत्यंत संवेदनशील बहस को जन्म दे दिया है यह घटना इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे एक कर्तव्यनिष्ठ प्रशासनिक या शैक्षणिक कार्रवाई को जातिगत रंग देकर कड़े सामाजिक कानूनों के दायरे में खींच लिया जाता है ऐसे में यह प्रश्न खड़ा होता है: क्या परीक्षा में अनुचित साधनों और नकल को रोकना भी अब अपराध की श्रेणी में आएगा? यह स्थिति अनिवार्य रूप से इस बात की मांग करती है कि समाज, न्यायपालिका और विधायिका इस कानून के बढ़ते दुरुपयोग और इसकी समीक्षा की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करें।

1. कर्तव्य का पालन बनाम कानूनी उत्पीड़न की विडंबना- आईआईटी बॉम्बे की घटना के तथ्य स्पष्ट करते हैं कि प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला केवल मिड-सेमेस्टर परीक्षा में निरीक्षक के रूप में अपनी ड्यूटी कर रहे थे उन्होंने छात्र को परीक्षा के स्थापित नियमों के विरुद्ध स्मार्टफोन से नक़ल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और नियमानुसार इसकी रिपोर्ट संस्थान को दी सीसीटीवी फुटेज और प्राथमिक पुलिस जांच के अनुसार छात्र बिना किसी तीखी बहस के शांत तरीके से अपना सामान समेटकर बाहर निकला और अपनी आखिरी फोन कॉल में भी उसने केवल अपनी गलती व शैक्षणिक तनाव का जिक्र किया, किसी जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न का नहीं।

इसके बावजूद प्रोफेसर डूला के विरुद्ध गंभीर कानूनी धाराओं में मामला दर्ज किया गया और उन्हें प्रशासनिक दायित्व से हटाकर अनिवार्य अवकाश पर भेजे जाने की कार्रवाई हुई। यह उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर दूला को कई शैक्षणिक उत्कृष्टता और शिक्षण उत्कृष्टता के परुस्कार मिल चुके है। उन्होंने इलेक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्ट पर कार्य किया है एवं विशिष्ट अनुसन्धान परियोजना पर भी कार्य कर रहे हैं।

इसके बाद साहिल के माता-पिता ने आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर डॉ. शिरीष केदारे और प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनशन शुरू कर किया। यह स्थिति निश्चित रूप से अत्यंत गंभीर और विडंबनापूर्ण है। एक ओर एक छात्र की दुखद मृत्यु ने उसके परिवार को गहरे आघात में डाल दिया है, वहीं दूसरी ओर उन संस्थान अधिकारियों और शिक्षक के विरुद्ध गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, जिनके विरुद्ध लगाए गए आरोप अभी न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं।

इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यही है कि यदि परीक्षा में नियमों का पालन करवाने वाला शिक्षक बाद में गिरफ्तारी और सार्वजनिक दबाव के भय में रहने लगे, तो भविष्य में कितने शिक्षक नकल या अनुशासनहीनता के मामलों में कठोर कार्रवाई करने का साहस करेंगे? शिक्षक यदि परीक्षा कक्ष में यह सोचने लगे कि नियमों का पालन करवाना कहीं उसके लिए कानूनी संकट न बन जाए, तो परीक्षा की शुचिता और पूरी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

2. एस.सी./एस.टी. अधिनियम के दुरुपयोग के ऐतिहासिक व न्यायिक उदाहरण- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को समाज के सबसे वंचित और शोषित वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने के पवित्र उद्देश्य से बनाया गया था। परंतु, समय के साथ इस कानून के कड़े प्रावधानों-जैसे कि बिना प्रारंभिक जांच के तुरंत एफआईआर और अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध-का उपयोग व्यक्तिगत दुश्मनी भुनाने, व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता समाप्त करने और प्रशासनिक दबाव बनाने के एक हथियार के रूप में किया जाने लगा है।

भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर इस कानून के बेलगाम दुरुपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कई ऐतिहासिक फैसलों में इसके उदाहरण सामने आए हैं:–

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018):इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था कि एस.सी./एस.टी. एक्ट का इस्तेमाल निर्दोष नागरिकों को ब्लैकमेल करने और लोक सेवकों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिए किया जा रहा है। अदालत ने पाया था कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कमी के कारण निर्दोष लोगों की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है।

हितेष वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य (2020): सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ किया कि किसी गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के बीच का हर विवाद स्वत: ही इस एक्ट के तहत अपराध नहीं बन जाता। जब तक कि विवाद का मुख्य कारण या मंशा पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने की न हो, तब तक इस कानून को लागू नहीं किया जा सकता।

देश की विभिन्न अदालतों (जैसे इलाहाबाद, दिल्ली और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय) ने जमीन के आपसी विवादों, पैतृक संपत्तियों के झगड़ों और यहां तक कि दफ्तरों में जूनियर-सीनियर के बीच होने वाली सामान्य प्रशासनिक कार्रवाइयों में दर्ज कराई गई झूठी एफआईआर को रद्द करते हुए टिप्पणी की है कि इस विशेष कानून का इस्तेमाल निजी प्रतिशोधके लिए एक औजार की तरह किया जा रहा है।

3. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े और जमीनी हकीकत- अधिनियम के दुरुपयोग की बात केवल मौखिक नहीं है, बल्कि देश की आधिकारिक सांख्यिकी भी इसकी गवाही देती है।राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पिछले पांच वर्षों के आंकड़े दर्शाते हैं कि एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों में एक बहुत बड़ा हिस्सा पुलिस जांच के बाद झूठा या गलतफहमी के रूप में बंद कर दिया जाता है।

4. कानून की समीक्षा और संशोधन क्यों अनिवार्य है? (तार्किक आधार)-किसी भी गतिशील और न्यायप्रिय समाज में कोई भी कानून पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। समय और परिस्थितियों के अनुसार कानूनों का मूल्यांकन और उनमें सुधार किया जाना आवश्यक है। एस.सी./एस.टी. अधिनियम की वर्तमान व्यवस्था निम्नलिखित कारणों से तात्कालिक समीक्षा की मांग करती है:

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन: इस कानून में आरोपी को अग्रिम जमानत न मिलना और शिकायत दर्ज होते ही बिना किसी प्राथमिक जांच के सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान है जो कि निर्दोषता के अनुमान (झ्रेल्स्जूदह द घ्हहदमहम) के सार्वभौमिक कानूनी सिद्धांत को कमजोर करता है, जहां सारा बोझ आरोपी पर आ जाता है कि वह खुद को बेगुनाह साबित करे।

प्रशासनिक पंगुता (Administrative Paralysis): सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, पुलिस और आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थानों में अधिकारियों और शिक्षकों के मन में यह निरंतर भय बना रहता है कि यदि वे किसी नियम तोड़ने वाले कर्मचारी या छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, तो उन पर तुरंत काउंटर-ब्लास्ट के रूप में इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। यह भय देश के प्रशासनिक ढांचे को कमजोर कर रहा है।

मुआवजा नीति का दुरुपयोग: वर्तमान नियमों के तहत एफआईआर दर्ज होते ही शिकायतकर्ता को एक निश्चित वित्तीय मुआवजा (आंशिक या पूर्ण) जारी कर दिया जाता है। कई आलोचकों और समाजशास्त्रियों का मानना है कि इस त्वरित वित्तीय लाभ के प्रावधान के कारण भी कई बार निहित स्वार्थों द्वारा झूठी प्राथमिकियां दर्ज कराने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

वास्तविक पीड़ितों के साथ अन्याय:जब इस विशेष कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है, तो समाज और व्यवस्था में इस कानून के प्रति एक अविश्वास की भावना पैदा होती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन वास्तविक और गंभीर पीड़ितों को उठाना पड़ता है जो ग्रामीण या सुदूर क्षेत्रों में आज भी भयंकर जातिगत अत्याचारों का सामना करते हैं। झूठे मामलों की बाढ़ के कारण असली पीड़ितों की आवाज दब जाती है।

5. संतुलन का मार्ग: सुधार के व्यावहारिक सुझाव

कानून की समीक्षा का अर्थ इसे समाप्त करना कतई नहीं है, बल्कि इसके दुरुपयोग के छिद्रों को बंद करना है। निम्नलिखित सुधारों के माध्यम से एक संतुलित ढांचा तैयार किया जा सकता है:–

अनिवार्य प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry): किसी भी लोक सेवक, शिक्षक या नागरिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस उप-अधीक्षकस्तर के अधिकारी द्वारा कम से कम 7 दिनों के भीतर एक त्वरित प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मामला कर्तव्य पालन या निजी विवाद का है अथवा वास्तव में जातिगत उत्पीड़न का।

न्यायिक छानबीन के बाद ही गिरफ्तारी: असाधारण मामलों को छोड़कर, जब तक पहली नजर में (Prima Facie) अपराध सिद्ध न हो या आरोपी के भागने का खतरा न हो, तब तक सीधे गिरफ्तारी पर रोक होनी चाहिए। झूठी शिकायतकर्ताओं पर दंडात्मक कार्रवाई: यदि अदालत में यह प्रमाणित हो जाता है कि शिकायत पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण, झूठी और प्रतिशोध की भावना से की गई थी, तो झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कड़ी दंडात्मक और वित्तीय कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए, ताकि कानून का मजाक बनाने वालों में डर पैदा हो।

निष्कर्ष–आईआईटी बॉम्बे की घटना देश की शिक्षा व्यवस्था और हमारे कानूनी ढांचे के लिए एक गंभीर चेतावनी है। परीक्षा में नकल रोकना या अनुशासन का पालन करवाना किसी भी दृष्टिकोण से अपराध नहीं हो सकता यदि हम अपने शिक्षकों को उनके कर्तव्य पालन के बदले जेल की सलाखें और सामाजिक प्रताड़ना देंगे, तो हम एक नैतिक रूप से दिवालिया समाज का निर्माण कर रहे होंगे।

संसद और सर्वोच्च न्यायालय को इस कानून के मूल उद्देश्यों की रक्षा करते हुए, इसके कड़े और एकतरफा प्रावधानों की गहन समीक्षा करनी चाहिए। न्याय का तराजू ऐसा होना चाहिए जो शोषितों को पूर्ण सुरक्षा दे, लेकिन किसी भी बेगुनाह को व्यवस्था की वेदी पर बलि चढ़ने से भी रोके।

–प्रो. (डॉ.) पी. सी. कंठालिया, पूर्व विभागाध्यक्ष (मृदा विज्ञान) एवं मुख्य वैज्ञानिक।

रामगंजमंडी क्षेत्र में बहने वाली 'पाटली नदी' जीर्णोद्धार के बाद फिर जी उठी

मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष-2024-25 में पाटली नदी की दशा सुधारने का बेड़ा उठाया गया

कोटा, (निसं)। रामगंजमंडी क्षेत्र में बहने वाली पाटली नदी वर्षों से अतिक्रमण, गंदगी से अटी पड़ी थी और प्रवाह क्षेत्र इस तरह बाधित था कि यह विलुप्त होने के कगार पर नजर आती थी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष-2024-25 में पाटली नदी की दशा सुधारने का बेड़ा उठाया गया, जिसके तहत हुए जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य की बदौलत इस नदी को मानो नया जीवन मिला है। नव निर्मित घाटों के बीच स्वच्छ बहती यह नदी आसपास के इलाके के लिए संजीवनी बनकर खुशी की लहर लाई है।

भारतीय सांस्कृतिक-भौगोलिक बसावट की तरह ही इस नदी के किनारे भी गांव, मंदिर, श्मशान घाट, विसर्जन घाट आदि मौजूद हैं। अत्यधिक अतिक्रमण तथा बहाव क्षेत्र में खानों का मलबा भरा हुआ था, जिससे इस नदी का बहाव क्षेत्र पूरी तरह बाधित हो गया था, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इस नदी से एक बड़ी मात्रा में पानी अनियंत्रित रूप से बहकर व्यर्थ चला जाता था, जिसका कोई उपयोग क्षेत्रवासियों को नहीं मिल रहा था।

अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग महेन्द्र कुमार ने बताया कि इस दुर्दशा को सुधारने के लिए नदी का सर्वेक्षण किया गया। इसके उपरांत इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024-25 में 5 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए, जिसका कार्य पूर्ण हो गया है और नदी अपने पुरातन स्वरूप में बहने लगी है।

रामगंजमण्डी क्षेत्र में स्थित पाटली नदी पुन: बहने लगी है।

ऐसे बदली सूरत :-मुख्यमंत्री बजट घोषणा अंतर्गत करवाए गए इस कार्य में पूरी नदी को अतिक्रमण मुक्त करके इसके बहाव क्षेत्र से मलबा हटाया गया। ऐतिहासिक जगह को देखते हुए जुल्मी हिरामन मंदिर के पास घाट का निर्माण कराया गया तथा मंदिर के पास पानी भराव के लिए पास में बने एनीकट का जीर्णोद्धार करवाया गया है तथा जुल्मी पुलिया के पास जहां जुल्मी गांव वालों के द्वारा मूर्ति विर्सजन किया जाता है, उस जगह घाट का निर्माण कार्य करवाया गया है, अमृतखेड़ी गांव के समीप श्मशान घाट के पास भी एक घाट का निर्माण कराया गया है तथा इसी तरह पायली गांव में मंदिर के पास भी घाट का निर्माण कराया गया है।

अधीक्षण अभियंता ने बताया कि चूंकि पाटली नदी से काफी मात्रा में पानी अनियंत्रित तरीके से बहकर चला जाता था, इस पानी को निकटवर्ती क्षेत्र में सिंचाई हेतु उपयोग लेने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024-25 में सुरेड़ा गांव के पास एक एनीकट की मरम्मत का कार्य भी करवाया गया है, जिसमें पानी संग्रहीत किया जा चुका है। इसी वर्ष जल ग्रहण विभाग द्वारा भी सेमल्हेड़ी के पास एक नए एनीकट का निर्माण किया गया है। इस नदी की पानी की आवक को देखते हुए नदी पर बांध बना कर इसके पानी से आसपास के क्षेत्र की भूमि को सिंचित करने के उद्देश्य से बजट घोषणा 2024-25 में डी.पी.आर का कार्य भी किया जा रहा है। जिसकी स्वीकृति के उपरान्त इस नदी के पानी से आसपास के क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

- **पाटली नदी वर्षों से अतिक्रमण, गंदगी से अटी पड़ी थी और प्रवाह क्षेत्र इस तरह बाधित था कि यह विलुप्त होने के कगार पर नजर आती थी**
- **मुख्यमंत्री बजट घोषणा अंतर्गत करवाए गए इस कार्य में पूरी नदी को अतिक्रमण मुक्त करके इसके बहाव क्षेत्र से मलबा हटाया**

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 29 सितम्बर, 2026

अश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत-2083, अश्विनी नक्षत्र प्रात: 9:04 तक, हर्षण योग रात्रि 3:20 तक, विष्टि करण सायं 5:11 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति– सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-मेष, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से दिन 9:04 तक है। राजयोग दिन 9:04 से सायं 5:11 तक है। भद्रा प्रात: 6:12 से सायं 5:11 तक रहेगी। आज तृतीया का श्राद्ध है। आज चतुरथी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया– चर 9:20 से 10:48 तक, लाभ अमृत 10:48 से 1:46 तक, शुभ 3:15 से 4:44 तक।

राहुकाल– 3:00 से 4:30 तक, सूर्योदय 6:22, सूर्यास्त 6:12

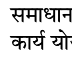

मेष
मानसिक तनाव दूर होगा। मन:स्थिति ठीक रहेगी। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे।

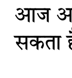

वृष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

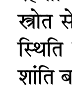

मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

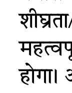

कर्क
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

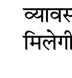

सिंह
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

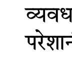

कन्या
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज यात्रा में परेशानी हो सकती है।

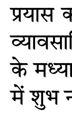

तुला
अपने अति कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। दिन के मध्यान्ह पश्चात चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है।

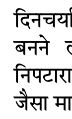

वृश्चिक
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

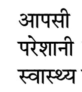

धनु
परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। घर-परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

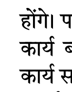

मकर
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

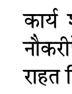

कुंभ
व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी।

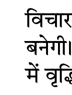

मीन
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। उचित कार्य योजना बनेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी।

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

उदयपुर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर, मंगलवार 29 सितम्बर, 2026

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

सेवा संकल्प अभियान — जन सेवा ही प्रभु सेवा

(17 सितम्बर - 17 अक्टूबर 2026)

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

सशक्त गांव, समृद्ध परिवार

विकास की ओर बढ़ता राजस्थान

अटल ज्ञान केंद्र

14,403 पंचायत मुख्यालय पर बनेंगे अटल ज्ञान केंद्र

ग्रामीण युवाओं के लिए बनेंगे रोजगार के बेहतर अवसर

अब तक 628 अटल सेवा केंद्र तैयार

जन सुविधाएं

- हर केंद्र पर 4 कंप्यूटर व हाई-स्पीड इंटरनेट
- आधुनिक ई-लाइब्रेरी की सुविधा
- ई-मित्र सेवाएं एक ही स्थान पर
- युवाओं के लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण)

820 रसोइयों का संचालन

प्रति थाली **लाभार्थी ₹8**, राज्य सरकार का **₹22 अनुदान**

6.87 करोड़ से अधिक भोजन थालियां परोसी गईं

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण) पर **₹180.89 लाख व्यय**

प्रत्येक रसोई में प्रतिदिन **200 थालियों की व्यवस्था**

स्वामित्व योजना

आम नागरिकों को ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित **भूमि / मकान के स्वामित्व का वैध दस्तावेज** देने की योजना

ग्रामीण परिवारों को **संपत्ति का स्वामित्व अधिकार प्राप्त**

राज्य में ड्रोन सर्वेक्षण कार्य लगभग पूर्ण

राज्य में **15.70 लाख** से अधिक स्वामित्व कार्ड वितरित

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से मैप-2 प्राप्त गांवों में स्वामित्व कार्ड वितरण शीघ्र

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

जोधपुर की फैक्टरी में लगी आग में झुलसे दो और फायर फाइटर की मौत

आगजनी की घटना में अब तक तीन फायर फाइटर की मौत हो चुकी है

जोधपुर, (कासं))। जोधपुर के बासनी स्थित फैक्टरी में आग लगने के बाद हुए ब्लास्ट के मामले में सोमवार को दो फायर फाइटर सुरेंद्र और प्रदीप की मौत हो गई। सुरेंद्र इस हादसे में 60 प्रतिशत तक झुलस गए थे। घटना में अब तक तीन फायर फाइटर की मौत हो चुकी है।

महात्मा गांधी हॉस्पिटल के सुपरिडेंटेंड डॉ. फतेह सिंह भाटी ने बताया कि 60 प्रतिशत तक झुलसने के बाद सुरेंद्र को वेंटिलेटर पर लिया था। सोमवार सुबह इलाज के दौरान सुरेंद्र की मौत हो गई। वहीं, प्रदीप वेंटिलेटर पर था, जो इस हादसे में 80 से 90 प्रतिशत तक झुलस गए थे। इलाज के दौरान सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे उसने भी दम तोड़ दिया। इससे पहले 26 सितंबर को एक फायर फाइटर प्रीतेश की मौत हो गई थी। डॉ. भाटी ने बताया कि जयपुर में एडमिट 6 मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रहा है। वहीं, चार मरीज प्रवीण, कुणाल, दुर्गेश और विनय का इलाज महात्मा गांधी हॉस्पिटल में चल रहा है।

इधर, इस हादसे में झुलसे फायर फाइटर्स के परिवार को राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी। इस हादसे में जान गंवाने वाले परिवार को राज्य सरकार की ओर से 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। कलेक्टर

- **जयपुर के अस्पताल में एडमिट छह मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है**
- **बासनी स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्टरी में 23 सितंबर की आग लग गई थी**

आलोक रंजन ने बताया कि इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी भी मिलेगी। उन्होंने बताया राज्य सरकार परिवार के साथ खड़ी है। इस हादसे में जो फायर फाइटर्स घायल हुए हैं, उन्हें पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा इस हादसे में घायल लगातार रिकवर हो रहे हैं, लेकिन, वे यदि काम पर नहीं जा पाते हैं तो परिवार के किसी एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी।

गौरतलब है कि बासनी की गणेश नगर श्रमिक कॉलोनी स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्टरी में 23 सितंबर की शाम करीब 5:30 बजे आग लगी थी। आग पर काबू पाने के लिए 35 फायर फाइटर्स की टीम पहुंची थी। कर्मचारी आग बुझाने में जुटे थे। इस दौरान छत से एक पत्थर केमिकल से भरे ड्रम पर आकर गिर गया था। इससे ब्लास्ट हो गया। इसमें फायर ब्रिगेड के कर्मचारी झुलस गए। दूसरे फायर फाइटर्स अपने साथियों को पिकअप और दमकल में लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे। आग इतनी भयानक थी कि रात 11 बजे के बाद एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड टीम को भी बुलाना पड़ा। 24 सितंबर की सुबह 5 बजे आग पर काबू पाया गया था, लेकिन सुबह 7 बजे आग फिर से धधक उठी, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। इस हादसे में झुलसे 14 कर्मचारियों में से 6 फायर फाइटर को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एंबुलेंस से महात्मा गांधी हॉस्पिटल से जयपुर अस्पताल भेजा गया था।

भरतपुर में शोरूम से लाखों की चोरी

भरतपुर, (निसं)। कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने एक शोरूम को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के ब्रांडेड कपड़े और नकदी चोरी कर ली। चोर चांदपोल गेट के पास स्थित ड्यूक शोरूम में ऊपर का गेट तोड़कर दाखिल हुए और वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शोरूम मालिक धीरेंद्र शर्मा निवासी मुखर्जी नगर ने बताया कि चोर शोरूम से करीब तीन लाख रुपये से अधिक कीमत के रेडीमेड कपड़े तथा गल्ले में रखे करीब 30 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए। वारदात से शोरूम संचालक को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। बताया गया कि चोरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले शोरूम के ऊपर रखे इन्वर्टर को बंद कर दिया, जिससे सीसीटीवी कैमरे भी बंद हो गए। इसके बाद चोर शोरूम में दाखिल हुए और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

अलग-अलग हादसों में दो की मौत

जोधपुर, (कासं)। निकटवर्ती मथानिया और बासनी एरिया में हुई सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के उपरांत परिजन को सुपुर्द किए।

मथानिया पुलिस ने बताया कि वैष्णव कॉलोनी तिंवरी निवासी जसराज सुथार की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उसके पिताजी माणकराम वैष्णव रविवार की शाम को बाइक लेकर तिंवरी से निकल रहे थे। तब एक गाड़ी चालक ने चपेट में ले लिया। हादसे में उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में अस्पताल में उपचार के बीच उनकी मौत हो गई।

इधर बासनी पुलिस के अनुसार मामा अचलेश्वर नगर सांगरिया निवासी काली ने रिपोर्ट दी कि उसका पति गोविंदराम आरजे ठेके के सामने से निकल रहा था। तब एक ट्रक चालक ने चपेट में ले लिया। हादसे में घायल उसके पति की अस्पताल में उपचार के बीच मौत हो गई।

बंध बरेठा अभयारण्य में पुलिस चौकी के पास सड़क पर दिखा लैपर्ड

रुदावल-भरतपुर (निसं)। भरतपुर जिले के बंध बरेठा वन्यजीव अभयारण्य इलाके में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात एक लैपर्ड (तेंदुआ) मुख्य सड़क पर बेफिक्र घूमता हुआ नजर आया। खास बात यह रही कि लैपर्ड पुलिस चौकी के ठीक सामने सड़क पर चहलकदमी कर रहा था। उसी दौरान वहां से गुजर रहे कार सवारों ने इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद लैपर्ड वापस जंगल की ओर लौट गया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, रविवार रात एक कार बंध बरेठा इलाके से गुजर रही थी। तभी अचानक पुलिस चौकी के पास सड़क पर लैपर्ड दिखाई दिया। कार सवारों ने वाहन धीमी कर लैपर्ड का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। गाड़ियों की हेडलाइट की रोशनी और हलचल महसूस होते ही लैपर्ड सड़क पार कर वापस सुरक्षित जंगल के घने इलाके में चला गया।

रेंजर राहुल फौजदार ने बताया कि हालिया वन्यजीव गणना के दौरान बंध बारैठा इलाके में कुल 6 लैपर्ड चिन्हित किए गए थे। यहां लेपर्ड्स का एक पूरा परिवार निवास करता है। जंगल से सटे होने के कारण ये अक्सर भोजन और पानी की तलाश में या सामान्य चहलकदमी के दौरान सड़क किनारे तक आ जाते हैं और स्थानीय लोगों या राहगीरों को दिखाई दे जाते हैं। बंध बारैठा का यह इलाका वन्यजीवों के लिए अनुकूल माना जाता है। इससे पहले मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से भटककर आया एक चीता भी इसी बंध बारैठा इलाके में कई दिनों तक डेरा डाले हुए था। बाद में वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर वापस कूनो भेजा था। प्रशासन और वन विभाग ने आसपास के ग्रामीणों एवं राहगीरों को रात के समय सतर्क रहने की सलाह दी है।

समान परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि कल तक

बीकानेर, (निसं)। शिक्षा सत्र 2026-27 में कक्षा 9वीं से 12वीं की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी। राज्य स्तरीय समान परीक्षा 2026-27 को लेकर शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए अंतिम मौका दिया है। कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 30 रुपए प्रति परीक्षार्थी शुल्क निर्धारित है।

सामान्य शुल्क के साथ भुगतान की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर रात 11:59 बजे तय की गई है। इसके बाद स्कूलों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। पहले शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 26 सितंबर निर्धारित थी, निर्धारित तिथि तक प्रदेश के 13 हजार निजी स्कूलों में से 50 फीसदी ने ही परीक्षा शुल्क जमा कराया है। विद्यार्थी हित को देखते हुए पूर्व निर्धारित 26 सितंबर की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर की गई है। राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा 15 से 29 अक्टूबर तक आयोजित होगी। 16 सितंबर से परीक्षा शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। अभी भी कई निजी स्कूल शुल्क जमा कराने से वंचित हैं।

अरविंद शर्मा, सहायक निदेशक, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान विभाग के संशोधित आदेश के अनुसार 1 से 10 अक्टूबर तक परीक्षा शुल्क जमा कराने पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 100 रुपए विलंब शुल्क देना होगा। वहीं 11 अक्टूबर से परीक्षा शुरू होने तक शुल्क जमा कराने वाले स्कूलों से 1,000 रुपए प्रति विद्यार्थी असाधारण विलंब शुल्क लिया जाएगा। ऐसे में समय पर शुल्क जमा नहीं कराने पर स्कूलों पर आर्थिक भार कई गुना बढ़ सकता है।

स्मैक सहित आरोपी गिरफ्तार

पावटा, (निसं)। विराटनगर थाना पुलिस ने स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4 ग्राम 29 मिलीग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस के अनुसार गठित टीम ने थाना क्षेत्र के सराय मोहल्ला वार्ड नंबर एक विराटनगर में कार्रवाई करते हुए प्रदीप कुमार उर्फ सीताराम पुत्र रामजीलाल को गिरफ्तार किया।

ट्रेन में तबियत बिगड़ने से कांस्टेबल की मौत

कोटा, (निसं)। ट्रेन में यात्रा के दौरान अचानक से तबियत बिगड़ने से एक सीआईएसएफ के कांस्टेबल की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यूपी निवासी सीआईएसएफ का जवान अपने अन्य साथियों के साथ मथुरा से ट्रेन में बैठकर कोटा आते समय ट्रेन में अचानक से तबियत बिगड़ गई। ट्रेन के कोटा पहुंचने पर जवान के अन्य साथियों ने उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया। जीआरपी पुलिस ने बताया कि आगरा उत्तरप्रदेश के निवासी कांस्टेबल उदय सिंह सिकरवार अपने अन्य साथियों के साथ देवली जाने के लिये मथुरा छावनी से ट्रेन से कोटा आ रहा था।

गैंगस्टर रोहित गोदारा का मकान तोड़ने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

मां की लगाई याचिका पर बीकानेर एसपी को जांच के आदेश दिये, 10 दिन में रिपोर्ट मांगी

बीकानेर, (निसं)। जिले के लूणकरणसर में गैंगस्टर रोहित गोदारा के मकान को बुलडोजर से ढहाने का मामला अब राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। मकान मालिक रोहित गोदारा की मां शकुंतला देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बीकानेर पुलिस अधीक्षक को शिकायत और दस्तावेजों की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दिए जाने वाले नए आवेदन पर गंभीरता से विचार किया जाए। अगर आरोपों में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है तो एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।

- **कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दिए जाने वाले नए आवेदन पर गंभीरता से विचार किया जाए**
- **अगर आरोपों में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है तो एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए**

जानकारी अनुसार, 13 जुलाई की रात लूणकरणसर कस्बे से करीब 16 किलोमीटर दूर तेजाणा ढाणी स्थित रोहित गोदारा से जुड़े दो मंजिला मकान पर अचानक जेसीबी चला दी गई। रात में पहुंचे लोगों ने मकान के पिछले हिस्से को पूरी तरह ढहा दिया। दीवारें तोड़ने के साथ मुख्य हिस्से के दरवाजे-खिड़कियां भी चोरी किए जाने का आरोप लगाया गया है। घटना के कई महीने बाद भी यह सवाल बना हुआ है कि मकान को आखिर किसने और किसके आदेश पर ढहाया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि घटना के समय पुलिस या प्रशासन की मौजूदगी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, अगर जांच में यह पुष्टि होती है कि आरोपियों ने अनधिकृत रूप से संपत्ति में प्रवेश किया या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। अब पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि मकान तोड़ने की घटना में किन लोगों की भूमिका थी और कार्रवाई किस आधार पर की गई।

रोहित गोदारा केवल राजस्थान या भारत में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर भी रहा है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े मामले में अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने अपनी चार्जशीट में भी रोहित गोदारा का नाम दर्ज किया था। अमेरिका की ओर से भारतीय अपराधियों और उनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कई गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी सामने आती रही है।

बीकानेर जिले में कई जगह बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में नुकसान

बीकानेर, (निसं)। दो दिन पहले तक 41 डिग्री सेल्सियस तापमान में तप रहे बीकानेर में देर रात अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश हुई। महाजन के आसपास कुछ गांवों में ओले गिरे, जबकि श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में तेज बारिश से गलियों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने बीकानेर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं महाजन क्षेत्र में तेज आंधी के दौरान बाइक असंतुलित होकर बस से टकराने से एक युवक की मौत हो गई।

महाजन में एक युवक महाजन-सरदारशहर रोड से अपने खेत की ओर फसल को बारिश से बचाने के लिए जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में तूफान इतना तेज था कि उसकी बाइक असंतुलित होकर बस से जा टकराई। हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान शेरपुरा निवासी भगवानदास के बेटे जगदीश प्रसाद के रूप में हुई है। महाजन में दिनभर की तेज तपिश और गर्मी के बाद रविवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। क्षेत्र के कई गांवों में बारिश हुई। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई, जबकि शेरपुरा की रोही में कई जगह बारिश के साथ ओले भी गिरे। इससे खेतों में पक चुकी फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। क्षेत्र के सुईं, शेरपुरा और बखुसर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में अचानक मौसम बदला। शेरपुरा की रोही में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।

श्रीडूंगरगढ़ के पास धीरदेसर चोटियान में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। करीब आधे घंटे तक लगातार बारिश होने से खेतों में पानी भर गया। बीकानेर के आसपास भी कुछ गांवों में बारिश हुई। बीकानेर शहर में बारिश नहीं हुई, लेकिन तेज हवाओं के साथ आए अंधड़ से लोगों को परेशानी हुई। कई घरों में मिट्टी भर गई। मौसम विभाग के अनुसार देर रात तक तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। अरजनसर के किसान मदनलाल ने बताया कि खेतों में मोठ की फसल पक चुकी है। ऐसे समय हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसल को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि जब फसल को बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब बारिश नहीं हुई और अब फसल पकने के बाद बारिश नुकसान पहुंचा रही है।

शाकम्भरी माता मंदिर की जमीन पर कब्जे का आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी उपखंड के पपुरना स्थित शाकम्भरी माता मंदिर परिसर की जमीन से कथित अवैध कब्जे हटाने की मांग को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने तहसीलदार सुभाषचंद्र को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मंदिर की भूमि का सीमा ज्ञान करवाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द करने की मांग की।

तहसीलदार को दिए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि पपुरना में शाकंभरी माता का प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसका पंजीयन भी विधिवत रूप से कराया हुआ है।

- **ग्रामीणों ने प्रशासन से मंदिर की भूमि का सीमा ज्ञान करवाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द करने की मांग की**

ग्रामीणों ने पपुरना में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग

ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ समय पूर्व कुछ लोगों ने कथित रूप से फर्जी पट्टे तैयार करवाकर मंदिर परिसर की जमीन पर कब्जा कर लिया तथा वहां तारबंदी कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि कथित फर्जी पट्टा प्रकरण का उन्होंने पुरजोर विरोध करते हुए मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था। इसके बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया गया था।

ग्रामीणों का कहना है कि इसके बावजूद मंदिर की भूमि पर किए गए कथित कब्जे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में स्थित नरसिंह भगवान के मंदिर से भैरव मंदिर तक के बीच के क्षेत्र की आबादी का सीमा ज्ञान करवाने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार सीमा ज्ञान के बाद मंदिर की भूमि पर किए गए कथित अवैध कब्जों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई कर सकेगा।

ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर निर्माण एवं व्यवस्था के लिए पूर्व में ग्रामीणों की बैठक कर जमीन उपलब्ध कराई गई थी। उनका आरोप है कि बाद में कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ के चलते मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया। इसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर मंदिर की भूमि का सीमांकन एवं सीमा ज्ञान कराया जाए तथा यदि जांच में कब्जा अवैध पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में मोहन सिंह, शेर सिंह, सुमेर सिंह, महिपाल सिंह, अमरसिंह, राजपाल सिंह, श्रीपाल सिंह और समुंद्र सिंह सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।

किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी की पत्नी ने किया सहयोग

जोधपुर, (कासं))। जिला पश्चिम में एक किशोरी को दंपती ने हवस का शिकार बनाया। आरोपी पति ने किशोरी से दुष्कर्म किया और उसकी पत्नी ने सहयोग दिया। किशोरी की मां का दंपती के घर पर आना जाना था। पीड़िता की मां की तरफ से अब केस दर्ज कराया गया है। घटना 15 सितंबर की है। जांच एसीपी स्तर के अधिकारी की तरफ से की जा रही है।

पुलिस के अनुसार पीड़िता की मां का आरोप है कि उसका एमपी के छोटेलाल के घर पर आना जाना था। उसके साथ में उसकी बेटी भी छोटेलाल के घर आती जाती थी। 15 सितंबर को छोटेलाल ने उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसमें उसकी पत्नी ने भी साथ दिया।

- **किशोरी की मां का दंपती के घर पर आना-जाना था**

पीड़िता की मां का आरोप है कि बेटी ने घटना की जानकारी रविवार को दी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अब जांच आरंभ की है।

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में सफाई व्यवस्था हेतु निविदा जारी की गयी हैं, जिसका यूबीएन **GSU2627WSRC00016** हैं। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी **http://sppp.rajasthan.gov.in** व **www.eproc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है।

राज.संवाद/सी/26/10835 वित्त नियंत्रक

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रपत्रों एवं लिफाफों के मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु दर संविदा जारी की गयी हैं, जिसका यूबीएन **GSU2627GLRC00017** हैं। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी **http://sppp.rajasthan.gov.in** व **www.eproc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है।

राज.संवाद/सी/26/10831 वित्त नियंत्रक

कार्यालय नगर परिषद् बांसवाडा (राज.)

फोन : 02962-243714, 247201, फैक्स : 02962-243714 Email Id :palika.bsw@gmail.com

क्रमांक : एफ 5( )निर्माण/न.प.बा./2026-2027/5558 दिनांक : 24.09.2026

निविदा सूचना स.15/2026-27

(NIB NO. DLB2627A7909)

सक्षम स्तर पर पंजीकृत संवेदक से कुल 05 निर्माण कार्य जिसकी कुल लागत 117.25 लाख हेतु ऑनलाईन निविदा डाउनलोड की अवधि दिनांक 25/09/2026 प्रातः 9 बजे एवं दिनांक 03/10/2026 सांय 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधित अन्य शर्ते एवं विवरण पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://eproc.rajsthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN No. DLB2627WSOB20470, 20471, 20472, 20473, 20474

आयुक्त नगर परिषद्, बाँसवाड़ा

राज.संवाद/सी/26/10796

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक :- राजकाज 24725723 दिनांक :- 26/09/2026

ई-बिड सूचना संख्या :- जोन विद्युत-प्रथम/21/2026-27

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से विद्युत कार्यों हेतु संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से विद्युत कार्यों हेतु BOT Basis पर ऑन लाईन बिड आमंत्रित की गई है। इन कार्यों की अनुमानित लागत, बिड बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, बिड शर्ते आदि का सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट **http://www.eproc.rajasthan.gov.in, www.jodhpurjda.org, www.sppp.raj.nic.in** पर देखा जा सकता है।

UBN No. : JOD2627WSOB00331

NIB Code : JOD2627A0178

राज.संवाद/सी/26/10824 अधिशाषी अभियंता (विद्युत-I)

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

निविदा सूचना (2026-27)

वृत कार्यालय (T&C) जोधपुर की निविदा संख्या-28 (2026-27) के अन्तर्गत 132 केवी जीएसएस शिव नगर के निर्माण के लिए अतिरिक्त अर्थिंग कार्य हेतु सक्षम ठेकेदारो/फर्मों से ऑफलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा के भरी जाने, खुलने तथा अन्य दिनांकों का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://energy.rajasthan.gov.in/rrvpn/#/home/dptHome, http://eproc.rajasthan.gov.in एवं "https://sppp.rajasthan.gov.in" पर उपलब्ध है।

UBN क्रमशः है - VPN2627WSOB01450

रा.रा.वि.प्र.नि./TR-7807/2026

राज.संवाद/सी/26/10861 अधीक्षण अभियन्ता (टी.एण्ड.सी.), जोधपुर

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

निविदा सूचना

220 केवी दूनी-जयपुर (साउथ) PGCIL और 220 केवी दूनी-कोटा PGCIL लाइनों और 220 केवी KTPS हीरापुरा डीसी लाइनों की रिस्ट्रिंगिंग (तार बदलना), लोकेशन नं. 1 (सकतपुरा) से लाकेशन नम्बर 506 (लीलो पॉइंट से 220केवी जयपुर साउथ लाइन तक, कुल लम्बाई 160 कि.मी.) डबल सर्किट टावर पर 06 कण्डक्टर हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा की पूर्ण जानकारी/निविदा की तारीख बढाने की सूचना के दस्तावेज/विवरण देखने/डाउनलोड करने के लिये (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in) एवम विभाग की वेबसाइट http://energy.rajasthan.gov.in/rrvpn पर उपलब्ध है। UBN No. VPN2627SSOB01435

रा.रा.वि.प्र.नि./TR-7800/2026

राज.संवाद/सी/26/10855 अधीक्षण अभियन्ता (प्र. एवं नि.), सवाई माधोपुर

Office of The Executive Engineer Water Resources Division, Rawatsar

Notice Inviting Bid

(NIB Code- WRN2627A0064)

On Behalf of the Governor of Rajasthan, this office invite e-Bid of work from Registered Experienced Qualified and Eligible Contractors. Nature of works are "Balance Work of 5 cs Discharging capacity, efficient Horizontal type electrical pumps (2 no of pumps each one on either side of IGMN) of 20 m lift in village Lune ki Dhani and Dabli Khurd with outfall into IGMC" of estimated cost Rs 18.28 lakh/-of invited from prospective bidders upto 29.09.2026 at 1.00 PM. Other particulars of the bids may be visited on the procurement portal http://www.eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in, of the state.

UBN Nos:- (WRN2627WSOB00177) Executive Engineer Water Resources Division Rawatsar

DIPR/C/16696/2026

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

CIN:- U40102RJ2000SGCO16484 (राजस्थान सरकार का उपक्रम)

सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, सूरतगढ़ (राज.)

ऑनलाईन/ऑफलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित वार्शिक अनुबंध/कार्य/सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जाती है:- 325(RVU2627WSOB01299) Raw water reservoir की मरम्मत, 326(RVU2627WSOB01305) HP हीटर को हटाने और नए HP हीटर लगाने का कार्य, 425(RVU2627GLOB01309) रोलर्स व आइडलर्स, 426(RVU2627GLOB01301) हाइड्रोलिक पंप और ऑयल सर्कुलेशन पंप, 427(RVU2627GLOB01304) साइड पैड लाइनर्स, 29(RVU2627GLOB01302) अग्निशामक यंत्र और नाइट्रोजन भरने की मशीन, 430(RVU2627GLOB01297) जर्नल शाफ्ट बेयरिंग, 431(RVU2627GLOB01298) LED लाइट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, 324(RVU2627WSOB01303) SSCTPS की सुरक्षा ऑडिट का कार्य, 327(RVU2627WSOB01300) पाइप रैक के स्टील स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन एवं 428 (RVU2627GSOB01306) UHMW पॉलीइथिलीन पैड की आपूर्ति। विस्तृत विवरण वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in (ई-निविदा हेतु), www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.energy.rajasthan.gov.in/rvunl पर उपलब्ध है।

RVUN/PR-4475

राज.संवाद/सी/26/10852 परियोजना प्रमुख (सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल)

जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक : जविप्रा/अ.अभि.-9/2026-27/डी-1216 दिनांक : 28.09.2026

निविदा सूचना

जविप्रा/अधि.अभि.-9/08/2026-27, Job No. : 185/2026-27

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा "Repair and Restrengtherning of BT Road In Mahal Yojana (A Block Extension block, C,D,E,F, Block) scheme Zone-09, JDA, Jaipur जिसकी अनुमानित लागत राशि रू. 177.00 लाख के लिए ऑनलाईन बिड्स दिनांक 09.10.2026 को 06.00 P.M. बजे तक आमंत्रित की जाती है निविदा बोली का ऑनलाईन आवेदन व भुगतान जविप्रा पोर्टल पर करने की अन्तिम तिथि 09.10.2026 को 06.00 P.M. बजे तक है।

निविदा बोली के दस्तावेजों का विस्तृत विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

(UBN No-: JDA2627WSOB00336)

निविदा में भाग लेने वालों को निम्न शर्तों की पूर्ति करनी होगी।

1. निविदादाता जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत हो एवं निविदा में भाग लेने के लिए बोलीदाता को आवेदन करने के लिए दस्तावेज शुल्क, अमानत राशि, आर.आई. एस.एल. प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन जमा करनी होगी।
2. ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने के लिए निविदादाताओं का राजस्थान सरकार के ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत हो।

राज.संवाद/सी/26/10873 अधिशाषी अभियन्ता-9

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

स्वास्थ्य भवन त्यागी बाटिक के सामने, जेलवेल रोड, बीकानेर-334001 फोन न-2226341 ईमेल-cmho-bik-r@nic.in

क्रमांक - एएनएम प्रशिक्षण / 2026-27/3228 **प्रेस-विज्ञप्ति** दिनांक 27-09-2026

श्रीमान् निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज, जयपुर के पत्र क्रमांक प्रशि/ एएनएम / एम-181/2026/272 दिनांक 24.09.2026 के अनुसरण के कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, त्यागी वाटिका के पास, स्टेशन रोड़, बीकानेर में दिनांक 29.09.2026 को प्रातः 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु पात्र अभ्यर्थियों को सत्र 2026-27 के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें कुल रिक्त सीटों के अनुसार जाति वर्गवार 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भिजवाया गया है। संबंधित अभ्यर्थी काउंसलिंग में निम्न वर्गानुसार योग्यता रखने वाले आवेदनकर्ता मय समस्त मूल प्रमाण-पत्र, अंकतालिका सहित निर्धारित समय पर उपस्थित होवें। ओबीसी / ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र एक वर्ष से पुराना ना हो। काउंसलिंग के लिये बुलावा रजिस्टर्ड डाक पत्र द्वारा अलग से भेज दिये गये है। बुलावा पत्र नहीं प्राप्त होने पर उक्त मैरिट रखने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु नियत तिथि को उपस्थित हो सकते है। उक्त प्रयोजन के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

	Category						Horizontal			
	GENERAL	DOB	SC	ST	MBC	EWS	AWW	ASHA	OL	Widow/Divorce
Cutoff	90.60	89.20	8760	83.20	84.80	84.40	43.20	55.20	65.40	72.83
DOB	23.02.09	06.09.07	06.12.06	30.06.09	04.04.07	07.07.08	01.01.92	30.06.97	12.05.06	15.02.99

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर
फोन नं. 0151-2226341, 2226344

DIPR/C/16698/2026

सार-समाचार

प्राधिकरण सचिव ने बाल गृहों एवं वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया

बांसवाड़ा (निसं)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पीयूष चौधरी ने जिला मुख्यालय पर स्थित जन कला साहित्य मंच संस्था की ओर से संचालित बालगृह अपना घर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य संस्थान में निवासरत बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लेना तथा उनके भोजन, आवास एवं देखभाल की स्थिति का मूल्यांकन करना था। निरीक्षण के दौरान चौधरी ने गृह के आवासीय कक्षों, रसोईघर, शौचालय, पेयजल व्यवस्था तथा स्वच्छता की स्थिति का अवलोकन किया। साथ ही उनके लिए उपलब्ध शैक्षिणक, मनोरंजनात्मक एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की भी समीक्षा की। चौधरी ने संबंधित प्रभारी को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा, खेलकूद एवं मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के एवं संस्थान प्रबंधन को शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। प्राधिकरण सचिव चौधरी ने राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि राजकीय संप्रेषण गृह का मुख्य उद्देश्य विधि से संघर्षरत बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उन्हें संरक्षण देना तथा सुधार, पुनर्वास एवं समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि यह गृह दंड का नहीं बल्कि सुधार और मार्गदर्शन का केंद्र है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संप्रेषण गृह में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, आवास व्यवस्था तथा रह रहे विधि से संघर्षरत किशोरों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। प्राधिकरण सचिव ने आवासीय कक्षों, भोजन व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संप्रेषण गृह के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संवाद कर संस्थान की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। इसी तरह नवजीवन वृद्धाश्रम के औचक निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण सचिव ने परिसर की स्वच्छता, आवास व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता, चिकित्सा सुविधाओं तथा सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण किया। उन्होंने रसोईघर, शयन कक्ष एवं सामुदायिक कक्ष का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमित स्वास्थ्य जांच, समय पर दवाइयों की उपलब्धता तथा मानसिक और भावनात्मक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पर्युषण महापर्व के समापन पर परम्परानुसार रथोत्सव निकाला

लोहारिया (निसं)। कस्बे में दिगम्बर जैन समाज के पर्युषण महापर्व के समापन पर बरसो से चली आ रही परम्परानुसार दो दिवसीय रथोत्सव का आयोजन सोमवार को हुआ। जिसके तहत भगवान पार्श्वनाथ निज मन्दिर से रजत गंधकुटी में श्रीजी को विराजमान कर साथ ही काष्ठ निर्मित विशाल रथ भी संतों के सानिध्य में नगर भ्रमण को निकला। गाजे-बाजे के साथ गैर नृत्य करते हुए श्रद्धालु जय घोष लगाते चल रहे थे। जगह जगह रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान श्रीजी का स्वागत अभिनंदन पूजन कर रहे थे। रथयात्रा स्टेट हाईवे पर स्थित बाहुबली मन्दिर पहुंची। कस्बे में सुबह से ही दूर-दूर से व्यापारी रथोत्सव में व्यापार निमित्त पहुंचें और कस्बे में 2 दिन तक मेले सा माहौल नजर आये। सायं वात्सल्य महाप्रसादी का आयोजन जैन नोहरे में हुआ। बाहुबली मन्दिर में भगवान की पूजा अर्चना महाआरती के पश्चात पुनः रथ यात्रा रवाना हुई और कस्बे के बीच सितारों वाले चौक पर दोनों ही रथ रात्री विश्राम निमित्त रुके। रात्री को सितारों वाले चौक पर महाआरती व सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। दूसरे दिन आज मंगलवार को पुनः अपरान्ह में सितारों वाले चौक से रथ यात्रा शुरु होगी। रथोत्सव के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व शांति व्यवस्था में अहम भूमिका निभाई।

आबकारी के राजस्व में गत वर्ष के मुकाबले 20 प्रतिशत वृद्धि हुई : नमित महता

उदयपुर। आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने कहा कि प्रदेश सरकार की अपेक्षा के अनुरूप राजस्व लक्ष्य के तहत स्टेट की ग्रोथ गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत है जो संतोषजनक है लेकिन निरोधात्मक कार्यवाहियों के तहत प्रगति वांछित है जिन जिलों में निरोधात्मक अभियान के दौरान अपेक्षा के अनुसार कार्य नही हुआ है वहां जिम्मेदारी तय कर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। आबकारी आयुक्त विडियों कांफ्रेंस के माध्यम से विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभागीय समीक्षा वीसी में राजस्व, निरोधात्मक गतिविधियों, बकाया वसूली के संबंध में विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

निरोधात्मक अभियान कार्यवाहियों के तहत आबकारी आयुक्त विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विभागीय समीक्षा बैठक लेते हुए।

आबकारी आयुक्त ने वीसी में प्रदेश में 14 से 30 सितंबर तक जारी विशेष निरोधात्मक अभियान की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में बीकानेर एवं उदयपुर में अवैध मदिरा परिवहन करते हुए 2 ट्रकों पर कार्रवाई हुई है जबकि प्रत्येक संभाग को कम से कम एक - एक अवैध मदिरा परिवहन के ट्रक पर कार्रवाई के निर्देश थे। इस संबंध में मुखबिर तंत्र की सहायता से प्रभावी योजना बनाकर कार्य की आवश्यकता है

आबकारी आयुक्त ने वीसी में निरोधात्मक अभियान की जोनवार समीक्षा करते हुए कोटा जोन की अवैध आईएमएफएल, देशी मदिरा, बीयर आदि की जब्ती पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित जोन उपायुक्त निरोधक दल हुकुम सिंह को अपेक्षित कार्रवाई करने को कहा एवं कमजोर प्रगति पर नोटिस देने के निर्देश प्रदान किए। इसी क्रम में क्रमवार अन्य जोन के समस्त निरोधक दल के जोन उपायुक्त को संबंधित जोन के जिलों में फील्ड विजिट कर निरोधक टीमों को मोटिवेट करने के निर्देश प्रदान किए। इस निरोधक कार्यवाही में पिछड़े धौलपुर, सीकर, बारां, टोंक, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, बाड़मेर को परफॉर्मेंस में सुधार के निर्देश दिए। आबकारी आयुक्त ने राजस्व लक्ष्य संबंधी समीक्षा करते हुए कहा कि गत वर्ष की तुलना में राजस्व के तहत स्टेट ग्रोथ अनुमानित 20 प्रतिशत है जिसे बनाए रखा जाना चाहिए। उन्होंने संतोषजनक प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी जोन को 20 से 25 प्रतिषत की राजस्व वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रगति को बनाए रखने के निर्देश दिए।

■ आबकारी आयुक्त ने विभागीय समीक्षा वीसी में अधिकारियों को निर्देश दिए

राजस्थान की यशोदा गमेती का भारतीय लैक्रोस टीम में चयन

■ ऑस्ट्रेलिया में देश का प्रतिनिधित्व करेगी

पैसिफिक कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज की छात्रा यशोदा गमेती।

उदयपुर। राजस्थान के लिए गर्व का क्षण है। पैसिफिक कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज, उदयपुर के फैकल्टी चेयरमैन प्रो.टी.पी. आमेटा ने बताया की छात्रा यशोदा गमेती का चयन भारतीय लैक्रोस दल में हुआ है। वह आगामी एशिया पैसिफिक लैक्रोस चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह प्रतिष्ठित चैंपियनशिप 4 से 11 अक्टूबर 2026 तक सनशाइन कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगी। राजस्थान लैक्रोस एसोसिएशन द्वारा जारी पत्र के अनुसार, इस चैंपियनशिप से पहले भारतीय टीम का तैयारी शिविर 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक शारदा यूनिवर्सिटी, आगरा में लगाया जाएगा। एसोसिएशन के सहायक सचिव महेन्द्र सिंह ने पैसिफिक कॉलेज के प्राचार्य को पत्र लिखकर यशोदा को 24 सितंबर से 11 अक्टूबर तक अवकाश प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि वह राष्ट्रीय शिविर और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सके। उल्लेखनीय है कि यह टूर्नामेंट 2028 ओलंपिक क्वालिफिकेशन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पडाव है। यशोदा के चयन से न केवल उनके कॉलेज बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। विवि के प्रेसिडेंट प्रोफेसर हेमंत कोठारी ने कहा कि इसी प्रकार से विद्यार्थियों के मनोबल को बढाने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

गीतांजली हॉस्पिटल में ''विश्व हृदय दिवस'' पर नागरिकों को स्वस्थ हृदय का संदेश दिया

गीतांजली हॉस्पिटल में विश्व हृदय दिवस पर 100 से अधिक वरिष्ठ नागरिक शामिल।

उदयपुर, 28 सितम्बर। गीतांजली हॉस्पिटल, उदयपुर एवं महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में विश्व हृदय दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए हृदय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में शहर के 100 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम की थीम यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट रही। कार्यक्रम में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. रमेश पटेल, डॉ. दिलीप जैन, डॉ. गौरव के. मित्तल, डॉ. रोहिन के. सैनी एवं हृदय सर्जरी विभाग से डॉ. संजय गांधी ने सहभागिता की। वहीं महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्थान से महासचिव भंवर सेठ, अध्यक्ष चोसर लाल कच्छावा एवं सचिव वरदान मेहता उपस्थित रहे।

■ 100 से अधिक वरिष्ठ नागरिक शामिल, विशेषज्ञों ने पैनल डिस्कशन में स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिए

पैनल डिस्कशन के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने वरिष्ठ नागरिकों को हृदय रोगों के कारण, बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार, शारीरिक सक्रियता, धूम्रपान से दूरी एवं तनाव प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। वरिष्ठ नागरिकों ने भी चिकित्सकों से हृदय स्वास्थ्य से जुडे सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने सरल एवं उपयोगी तरीके से समाधान किया। हेड मार्केटिंग कल्पेश चंद रजबार ने कहा कि गीतांजली हॉस्पिटल द्वारा समय-समय पर इस प्रकार के स्वास्थ्य एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आमजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा समय पर जांच एवं स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रेरित करना है।

दो करोड़ रिश्वत मामले में कई अनियमितताएं उजागर हुई

उदयपुर, (का.स.)। उदयपुर में दो करोड़ रिश्वत मामले में गिरफ्तार एसओजीके एएसपी मुकेश कुमार सोनी और उसके दलाल सज्जन सिंह जैन से जुड़े कई खुलासे हुए हैं। शिकायतकर्ता निरंजन मोगरा ने बताया. एएसपी और दलाल से कार में मेरी मुलाकात हुई थी। इस दौरान जाते.जाते एएसपी सोनी ने कहा था. मैं 30 सितंबर को चार्जशीट पेश कर दुंगा। इससे पहले व्यवस्था कर देना। निरंजन मोगरा का आरोप है कि मेरे घर से सोने की घड़ी,बैंगल और डीवीआर जब्त की गई थी। एएसपी मुकेश सोनी ने इन्हें रिकॉर्ड में नहीं दर्शाया। इनकी कीमत करीब 6.7 लाख रुपए थी। जब 25 अगस्त को जमानत के बाद हम घर आए तो पता लगा कि जब्त हुई चीजें घर पर नहीं हैं।निरंजन मोगरा ने बताया. सज्जन सिंह ने मुझे 100 प्रतिशत काम होने की गारंटी दी थी।

■ आरोप- रिकॉर्ड में नहीं दिखाया

■ 30 सितंबर से पहले रुपए देने को कहा था

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर

Phone No:-6367304312 Email:-cmho-uda-rj@nic.in

क्रमांक:प्रशि./म.स्वा.का./2026/5606 दिनांक :25-09-2026

काउन्सलिंग में उपस्थित होने की सूचना बाबत्

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 272 दिनांक 24.09.2026 की पालना में इस कार्यालय के अधीन संचालित महिला स्वास्थ्य कार्यकता प्रशिक्षण केन्द्र, सलूम्बर में वर्ष 2026-27 में प्रशिक्षण हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच उपरान्त दिनांक 29.09.2026 को आयोजित होने वाली काउन्सलिंग हेतु 5 गुना अभ्यर्थियों की कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है।

श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स का विवरण

क्र.सं.	श्रेणी	कट ऑफ मार्क्स का प्रतिशत	जन्म तिथि
1	सामान्य	89.80	14.06.2009
2	आर्थिक पिछड़ा वर्ग	84.20	19.06.2007
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	87.60	22.07.2007
4	अति पिछड़ा वर्ग	50.00	23.08.1991
5	अनुसूचित जाति	85.60	05.09.2008
6	अनुसूचित जाति -टीएसपी	78.00	31.08.2006
7	अनुसूचित जनजाति	87.80	01.01.2009
8	अनुसूचित जनजाति -टीएसपी	77.40	12.05.2007
9	आंगनबाडी कार्यकर्ता	50.20	02.02.1989
10	विधवा/तलाक शुदा	69.60	15.01.1996
11	दिव्यांग एक पैर (O.L.)	40.76	22.11.1988
12	आशा सहयोगिनी	40.76	22.11.1988

नोट:-

10. काउन्सलिंग हेतु बुलावा पत्र अलग से डाक द्वारा भिजवा दिया गया है।
11. काउन्सलिंग हेतु निर्धारित सीटों की संख्या के 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है।
12. काउन्सलिंग हेतु किसी भी तरह का यात्रा भत्ता व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा।
13. किन्हीं कारणों से बुलावा पत्र नहीं मिलने की स्थिति में उक्त श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स रखने वाले अभ्यर्थी काउन्सलिंग हेतु नियत तिथि, नियत स्थान एवं नियत समय पर उपरिथत होवें।
14. टीएसपी श्रेणी में उदयपुर एवं सलूम्बर जिले के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
15. काउन्सलिंग हेतु पात्र समस्त श्रेणी के आवेदकों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है।
16. काउन्सलिंग हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल दस्तावेज के साथ उपथिति देवें।
17. आंगनबाडी एवं आशा श्रेणी के आवेदकों को 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र साथ में लाना होगा तथा आशा सहयोगिनी को आशा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 6 एवं 7 के चतुर्थ चरण तक के प्रमाण पत्र साथ में लावें।
18. काउन्सलिंग का समय प्रात: 09:00 बजे से मध्यान्ह 05:00 बजे तक रहेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर

Name Changed
I Have Changed My Name From Tahira to Tahira Salumbarwala For All Purposes. In Future be called and Known by New Name. R/o H.No.10 G, Kharol Colony, Fatehpura, Udaipur, Raj.

Name Changed
I Have Changed My Name From Fakhruddin to Fakruddin Falasiya For All Purposes. In Future be Called and Known by New Name. R/o 10 Choti Boharwadi, Bada Bazar, Udaipur, Raj.

गांधी जयंती से पूर्व उत्कृष्ट कार्यकरताओं का सम्मान होगा

उदयपुर (कासं)। राजीव गांधी पंचायती राज संघ उदयपुर की व से गांधी-शास्त्री जंयती के उपलक्ष्य पर 1 अक्टूबर को गांधी ए शास्त्री जयंती की पूर्व संध्या पर मुखर्जी चौक पर सफ़ाई कम्यिों ए नरेगा कर्मियों, छात्र-छात्राओ, समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान कर गांधी स्मरण किया। पंचायती राज संघ के जिला अध्यक्ष एवं पार्षद वार्ड 22 हिदायत तुल्ला ने बताया कि हर वर्ष इस मौके पर वार्ड 8 में गांधी मूर्ति पर सफाई कर्मीयों, नरेगा कर्मीयों, समाज के प्रबुध जनों का प्रशस्ति पत्र एवं पारितोषिक वितरण कर सम्मान किया जाता है।

कार्यालय ग्राम पंचायत ऋषभदेव पंचायत समिति ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-273 दिनांक-24/09/26

-: अल्पकालीन सीमित निविदा सूचना 2026-27:-

ग्राम पंचायत ऋषभदेव में करवाये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यो के उपापन की सीमित निविदाएं दिनांक 28/09/2026 को प्रात: 11.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/ जानकारी **https://www.sppp.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।

NIB Code -ZUD2627A2364
UBN is -ZUD2627GSLB02810

प्रशासक	ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ऋषभदेव	ग्राम पंचायत ऋषभदेव
पं.स. ऋषभदेव	पं.स. ऋषभदेव
जिला उदयपुर	जिला उदयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत माण्डवाफला पंचायत समिति ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-35 दिनांक-28/09/26

-: अल्पकालीन खुली बोली ई निविदा सूचना :-

ग्राम पंचायत माण्डवाफला पंचायत समिति ऋषभदेव में निर्माण कार्यो हेतु इच्छुक एवं उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से ई निविदा दिनांक 30/09/2026 को दोपहर 12 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/ जानकारी **sppp.rajasthan.gov.in** व **eproc.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।

UBN No-ZUD2627WSOBO2869,70

प्रशासक	ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत माण्डवाफला	ग्राम पंचायत माण्डवाफला
पं.स. ऋषभदेव	पं.स. ऋषभदेव
जिला उदयपुर	जिला उदयपुर

राजस्व से लेकर कृषि, सामाजिक सुरक्षा से पशु बीमा तक का मिल रहा लाभ

उदयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेशभर में संचालित विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत गिरदावर सर्कल स्तर पर विशेष जन सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को विभिन्न विभागों से जुडी सेवाएं और योजनाओं का लाभ उनके नजदीक ही उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद प्रीतम कुमार के निर्देशन में आयोजित हो रहे इन शिविरों में ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है। शिविरों में राजस्व, कृषि, सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहकर आमजन के प्रकरणों का निस्तारण कर रहे हैं। विशेष रूप से राजस्व संबंधी मामलों में नामांतरण, खाता दुरुस्ती, भूमि संबंधी रिकॉर्ड में सुधार सहित अन्य कार्यों के लिए ग्रामीणों को अब संबंधित कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड रहे हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जो लंबे समय से लंबित थे और शिविर में अधिकारियों की तत्परता एवं विभागीय समन्वय से उनका मौके पर ही समाधान हुआ।

ग्राम पंचायत लुणदा में विशेष शिविर में ग्राम आम्बा का कुआ निवासी भंवरलाल पुत्र गौकल को उनके पुस्तैनी मकान का पट्टा हाथों-हाथ प्रदान किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। शिविर में कानोड़ तहसीलदार बगदाराम राणा, सहायक विकास अधिकारी श्री शम्भुलाल मीणा, ग्राम पंचायत लुणदा की प्रशासक श्रीमती गोदावरी देवी धाकड़ सहित जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

ग्राम पंचायत छाणी में आयोजित शिविर में राजस्व ग्राम कातर निवासी प्रतापसिंह पुत्र कूरसिंह की करीब 12 वर्षों से लंबित समस्या का समाधान हुआ। ग्राम पंचायत बावलवाड़ा में आयोजित विकसित भारत जन सेवा अभियान के शिविर में किसान शंकर पुत्र श्री मंगला की फार्मर रजिस्ट्री से जुडी समस्या का मौके पर समाधान किया गया। शंकर लंबे समय से अपनी कृषि भूमि की फार्मर रजिस्ट्री करवाने के लिए प्रयासरत थे।

रजिस्ट्री नहीं होने से उन्हें फसल बीमा और कृषि अनुदान सहित विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई आ रही थी। शिविर में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की और उन्हें फार्मर रजिस्ट्री कार्ड उपलब्ध कराया। अपनी समस्या के तत्काल समाधान पर किसान शंकर ने राजस्थान सरकार एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

रेंटल पॉलिसी की प्रक्रिया प्रांरभ

उदयपुर। जिले में रीको द्वारा विकसित किये गये विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में राइजिंग राजस्थान में एमओयू करने वाले निवेशकों के लिए औद्योगिक/व्यावसायिक भूखण्डो के प्रत्यक्ष आवंटन/ई-नीलामी/रेंटल पॉलिसी की प्रक्रिया सोमवार 28 सितम्बर से प्रांरभ की जा चुकी है। इसके अन्तर्गत औद्योगिक भूखण्डों के आरक्षित मूल्य पर चार औद्योगिक क्षेत्रों के कुल 162 औद्योगिक भूखण्डों के प्रत्यक्ष आंवटन के चौहदवें चरण की प्रक्रिया प्रारंभ की है। योजनान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र कलडवास (विस्तार), आमली, औद्योगिक क्षेत्र सगतपुरा (भीण्डर) व श्रीराम जानकी औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र, माल की टूस के औद्योगिक भूखण्ड शामिल हैं। रीको के अतिरिक्त महाप्रबन्धक अजय पण्ड्या ने बताया कि योजनान्तर्गत धरोहर राशि 28 सितम्बर प्रात: 10 बजे से 12 अक्टूबर सायं 6:00 बजे तक जमा कराई जा सकेगी। किसी भी भूखण्ड पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ई-लॉटरी 15 अक्टूबर को की जायेगी। पण्ड्या ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र कलड़वास (विस्तार) में 2 औद्योगिक भूखण्ड, औद्योगिक क्षेत्र आमली में 60, औद्योगिक क्षेत्र सगतपुरा (भीण्डर) में 90, एवं औद्योगिक क्षेत्र श्रीराम जानकी माल की टूस में 10 औद्योगिक भूखण्डों को प्रत्यक्ष आंवटन योजना के चौहदवें चरण में रखा गया है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये 06, महिला उद्यमियों के लिये 4, भूतपूर्व सैनिको के लिये 1, बैचमार्क दिव्यांगजनों के लिये 3 तथा सशस्त्र बलों के शहीदो के आश्रितो के लिये 1 भूखण्ड आरक्षित है।

नव निर्वाचित सभापति सुशीला गुप्ता का अभिनन्दन

प्रदेश उपाध्यक्ष पारस खुरदिया एवं जिला अध्यक्ष प्रवीण नाहर ने उन्हें पगड़ी एवं उपरना पहनाकर अभिनन्दन किया।

उदयपुर,(निसं)। नगर निगम चुनाव 2026 में डूंगरपुर नगर निगम की नव निर्वाचित सभापति सुशीला गुप्ता के प्रथम बार उदयपुर आगमन पर उनके निज आवास पर मेवाड विकास मंच एवं कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आत्मीय अभिनन्दन किया गया। कार्यक्रम में कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजश्री गांधी के सानिध्य में सुशीला गुप्ता का उपरना एवं उपहार भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए जनसेवा एवं नगर विकास के लिए उनके सफल कार्यकाल की मंगलकामना की गई। इस अवसर पर उपस्थित स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के. के. गुप्ता का भी संगठन की ओर से सम्मान किया। राष्ट्रीय समन्वयक शिरीष नाथ माथुर, प्रदेश उपाध्यक्ष पारस खुरदिया एवं जिला अध्यक्ष प्रवीण नाहर ने उन्हें पगडी व उपरना पहनाकर अभिनन्दन किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों व गणमान्यजनों ने नव निर्वाचित सभापति सुशीला गुप्ता को बधाई दी, डूंगरपुर के विकास, स्वच्छता व जनहित के कार्यो में सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा व्यक्त की।

SRG HOUSING FINANCE LIMITED

एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

CIN: L65922RJ1999PLC015440
321, एस.एम. लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्किल के पास, उदयपुर - 313001 (राजस्थान)
दूरभाष : 0294-2412609, ईमेल: info@srghousing.com, वेबसाइट: www.srghousing.com

परिशिष्ट - 4 {नियम 8 (1)} सांकेतिक की सूचना (स्थावर संपत्ति के लिए)

अधोहस्ताक्षरी, जो एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है, ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत निम्न ऋणी/सहऋणी/जमानतियों/बन्धककर्ता को एक मांगपत्र जिसमें उल्लेखित रकम, जो उक्त सूचना पत्र की प्राप्ति की तारीख से 60 दिवस के भीतर प्रतिदाय करने के लिए ''मांग पत्र'' जारी किया था। ऋणी/सहऋणी/जमानतियों/बन्धककर्ता द्वारा रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर ऋणी, सहऋणी, बन्धककर्ता, उनके जमानतदारों एवं जनसाधारण को यहाँ सूचना दी जाती है की अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002, के नियम 8 के अंतर्गत निम्न संपत्तियों का सांकेतिक कब्ज़ा उल्लेखित दिनांक को ले लिया है। ऋणी सहऋणी, बन्धककर्ता व जमानतदारो को विशिष्ट रूप से एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से इसके द्वारा सावधान किया जाता है की वह नीचे वर्णित संपत्तियों के सम्बन्ध में कोई व्यवहार नही करे। इन संपत्तियों के सबंध में किया गया कोई भी व्यवहार नीचे **सांकेतिक कब्ज़ा** पत्र में वर्णित रकम, और सांकेतिक कब्ज़ा पत्र की दिनांक से आगे के ब्याज, खर्चो, अन्य खर्चो आदि के लिए एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 321, एस.एम. लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्किल के पास, उदयपुर - 313001 (राजस्थान) के प्रभार के अधीन होगा। अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के अंतर्गत सुरक्षित (सिक्योर्ड) प्रतिभूति के उन्मोचन के लिए उपलब्ध समय के प्रावधानों की ओर ऋणी, सहऋणी, बन्धककर्ता व उनके जमानतदारो का ध्यान आकृष्ट करता है।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या/ ऋणी/ सहऋणी/ जमानती	1) मांग पत्र की दिनांक 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार	स्थावर संपत्ति का विवरण
1.	HLR0000000015962 श्री बलवंत कुमार मीणा पुत्र श्री खेमराज मीणा (ऋणी) श्रीमती निमिषा पत्नी श्री सुरेन्द्र (सह- ऋणी-1) श्रीमती प्रियंका डिन्दोर पत्नी श्री मोहनलाल डिन्दोर (सह- ऋणी-2) श्री खेमराज कालासुआ पुत्र श्री जगन्नाथ कालासुआ (सह- ऋणी-3) श्री संजय कुमार मीणा पुत्र श्री बसंत लाल मीणा (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- अक्टूबर 13, 2025 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- सितम्बर 22, 2026 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार- ₹ 9,80,420/- रुपये नौ लाख अस्सी हज़ार चार सौ बीस मात्र दिनांक अक्टूबर 07, 2025 तक एवं अक्टूबर 08, 2025 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्री खेमराज पुत्र श्री जगन्नाथ कालासुआ मीणा की सम्पति पट्टा सं.-01, खसरा सं.-490, संकल्प सं.-01, ग्राम-सकानी, ग्राम पंचायत-सकानी, तहसील-आसपुर, जिला-डूंगरपुर (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 2009.00 वर्ग गज है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व- सह-ऋणी की जमीन, पश्चिम- सह- ऋणी की जमीन, उत्तर- सह-ऋणी की जमीन, बाद मुख्य रास्ता, दक्षिण- सह-ऋणी की जमीन
2.	HLR0000000023182 श्री हरीश कलाल पुत्र श्री रूप लाल कलाल (ऋणी) श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री हरीश कलाल (सह- ऋणी) श्री हिरा लाल पटेल पुत्र श्री केवा जी (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- जून 08, 2026 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- सितम्बर 22, 2026 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार- 16,07,260/- रुपये सौलह लाख सात हज़ार दौ सौ साठ मात्र दिनांक जून 08, 2026 तक एवं जून 09, 2026 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री हरीश कलाल की सम्पति प्लाट सं. -41, आराजी सं.-4415/2746, 4446/2758, 4417/2759, ग्राम- डाकन कोटड़ा, तहसील-गिरवा, जिला-उदयपुर (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1500.00 वर्ग फीट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व-प्लाट सं.- 42, पश्चिम-प्लाट सं.- 40, उत्तर- प्लाट सं.- 66, दक्षिण -40 फीट चौडी सड़क
3.	HLR0000000014146 श्री शान्ति लाल भाटिया पुत्र श्री शंकर लाल भाटिया (ऋणी) श्रीमती आशा भाटिया पत्नी श्री शान्ति लाल भाटिया (सह- ऋणी-1) श्री भगवतीलाल भाटिया पुत्र श्री शंकर लाल भाटिया (सह- ऋणी-2) श्री भावेश भाटिया पुत्र श्री अशोक भाटिया (जमानती-1) श्री मगन लाल पाटीदार पुत्र श्री हुकाजी पाटीदार (जमानती-2)	1) मांग पत्र की दिनांक- सितम्बर 13, 2025 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- सितम्बर 22, 2026 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार- ₹ 12,65,850/- रुपये बारह लाख पैंसठ हज़ार आठ सौ पचास मात्र दिनांक सितम्बर 08, 2025 तक एवं सितम्बर 09, 2025 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्री भगवतीलाल भाटिया पुत्र श्री शंकर लाल भाटिया की सम्पति पट्टा सं.- 1772 (आराजी सं.- 1729), संकल्प सं. - 12, ग्राम-नयागाव, ग्राम पंचायत-सामलिया, तहसील-सागवाड़ा, जिला-डूंगरपुर (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1219.00 वर्ग फीट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व- स्वयं की ज़मीन, पश्चिम-स्वयं का आगन और मोहल्ला रास्ता, उत्तर-रेवा पत्नी श्री स्वर्गीय दाल जी भाटिया का मकान, दक्षिण- आम रास्ता सी.सी. सड़क

स्थान-राजस्थान
प्रकाशन की दिनांक- 29/09/2026

अधिकृत अधिकारी
एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कांग्रेस नेतृत्व को देश व संवैधानिक संस्थाओं से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए : राठौड़

■ कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर तो कभी चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा कर फोड़ते है

उदयपुर (कासं)। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठोड़ ने कहा कि पार्टी के पिछले दिनों हुए चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र रूप से सम्पन्न हुए है। कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जब चुनाव हारते है तो अपनी हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर तो कभी चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा कर फोड़ते है। चुनाव आयोग के पूर्ण और सर्वसम्मत बयान के बाद कांग्रेस नेतृत्व को देश और संवैधानिक संस्थाओं से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया है।

राठोड़ सोमवार को यहाँ आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस को सम्बोधित कर रहे थे। राठौड़ ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनो चुनाव आयुक्त डॉ. एस.एस. संधू, डॉ. विवेक जोशी ने संयुक्त प्रेस स्टेटमेंट जारी कर कहा कि देश भर में संचालित एसआईआर सहित सभी प्रमुख निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए है। विपक्ष द्वारा लगातार फार्म 6 को लेकर जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है जिस पर चुनाव आयुक्त ने कहा कि एसआईआर के लिए फार्म 6 से संलग्न घोषणा पत्र को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्णत: सही व वैध ठहराया है।

भाजपा की नीति और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के विजन एवं किये गये कायी को राजस्थान की सरकार ने सराहा है और राजनस्थान की 10 में से 9 नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बना है। विगत बोर्ड में विकास के किये गये कार्यों की बदौलत ही शहर में पार्टी का 7 वा बोर्ड बना है।

एक सवाल के जवाब में सिंघवी ने कहा कि शहर में किसी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, चाहे वह पार्टी के किसी बडे पदाधिकारी का ही क्यों न हो। फुटपाथ पर किए गए अतिक्रम को हटाये जायेंगे। शहर में पानी के 72 घंटे में पेयजल की व्यवस्था को लेकर कांग्रेस शहर का वातावरण दुषित कर रहे है। उन्होंने कहा कि पानी को 48 घंटे में देने की व्यवस्था को लेकर सम्बंधित अधिकारियों ने चर्चा की जा रही है दो घंटे की बजाय एक घंटे ही पानी दे और तेज दबाव के साथ दे।

सिंघवी ने कहा कि शहर में बनने वाली एलिवेटेड रोड जहाँ भी 90 डिग्री का कर्व आ रहा है उसे अधिकारियों के साथ मिल बैठ दुरूस्त किया जायेगा। सेक्टर 4 की मुख्य रोड़ पर लोगों ने अपना निवास बना दिया है जिसे दो दिन के अंदर हटा दिया जायेगा।

प्रेसवार्ता में संभाग मीडिया प्रभारी चंचल अग्रवाल, महामंत्री देवीलाल सालवी, पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक, डॉ. पंकज बोराणा, पार्षद अशोक नागदा, प्रकाश अग्रवाल, शहर मीडिया प्रभारी सीमा चम्पावत, कृष्णकांत कुमावत, दुदाराम डांगी, गोविन्द दीक्षित, डॉ. ओम पारीक, हरीश कुमावत, दीपक कुमावत, राजेश स्वर्णकार सहित पदाधिकारी उपस्थित थे।

सार-समाचार

भगत सिंह की जयंती पर 106 लोगों ने रक्तदान कर श्रद्धांजलि अर्पित की

उदयपुर (कासं)। शहीद.ए.आजम भगत सिंह की जन्मजयंती के उपलक्ष्य में जी6 फार्मेसी एवं रक्तदाता युवा वाहिनी के संयुक्त तत्वावधान में श्रद्धांजलि स्वरूप रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 106 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर अमर शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और जरूरतमंद मरीजों के लिए मानवता की सेवा में अपना योगदान दिया। शिविर संयोजक अनुप औदिच्य ने बताया कि रक्तवीर भाई.बहनों को उपरना ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र एवं तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा एवं दिनेश श्रीमाली बतौर अतिथि उपस्थित रहे।

पुलिस हिरासत से दो बंदी भागे

उदयपुर (कासं)।चोरी की वारदात का मौका निरीक्षण करने के दौरान नाबालिग दो बंदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के बडगांव थाना क्षेत्र टाईगर हिल स्थित मकान से हथियार चोरी करने के मामले में पुलिस ने गत दिनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। चार दिन पूर्व आरोपियों को पुलिस मौका नक्शा के लिए लेकर गई थी। इस दौरान दो नाबालिग पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस की टीमें फरार नाबालिगों की तलाश में जुटी है।

नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित

उदयपुर (कासं)। उदयपुर सैनिक विश्राम गृह में संविदा के आधार पर सहायक के पद पर पूर्व सैनिक की नियुक्ति की जानी है। सिपाही या नायक से सेवानिवृत्त इच्छुक पूर्व सैनिक जिसकी आयु 58 वर्ष से कम हो जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में उपस्थित होकर अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल कमलेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि संविदा पर सहायक के पद पर चयन विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम के किया जायेगा। उन्होंने बताया कि नियुक्ति पूर्णतया संविदा पर होगी और अमलगमेटेड फण्ड द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा। विस्तृत जानकारी एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु 03 दिन में कार्यालय समय में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

उदयपुर में मादक पदार्थ तस्कर की संपत्ति सीज़

उदयपुर (कासं)। जिले के बैकरिया थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्ति मकान व नोहरे को सीज किया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक डूंगरसिंह के सुपरविजन में बैकरिया थानाधिकारी रामावतार मीणा के नेतृत्व में टीम ने कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी एवं अवैध गतिविधियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उदयलाल उर्फ उदा पुत्र रतनलाल गुर्जर निवासी पेमाखेड़ा बिजयपुर चित्तोड़गढ़ के नाम पर दो मंजिला आवासीय मकान व एक नोहरा निजकी कीमत 55 लाख रूपये है उक्त दोनों संपतित को फ्रीज किया गया। उक्त संपत्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा स्थाई अनुमोदन किये जाने पर कार्यवाही की गई है।

हत्या का मामला दर्ज

उदयपुर (कासं)। फलासिया थाना पुलिस ने आरोपी व साथी के खिलाफ व्यक्ति की हत्या करने का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित भुवनेश पुत्र सुखलाल दामा निवासी बिजली फलासिया ने आरोपी बिजली निवासी भंवरलाल व साथी के खिलाफ पिता सुखलाल की हत्या करने का प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि आरोपियों ने 23 सितंबर को सुखलाल के साथ मारपीट की थी। जिसके चलते उनकी मौत हो गई। 26 सितंबर को सुखलाल का शव मिला जिसमें कीडे पड़ चुके थे। इस मामले में पुलिस ने 27 सितंबर को मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया था। प्रकरण की जांच फलासिया थानाधिकारी वेलाराम कर रहे है।

मंदिर से चांदी व नकदी चोरी

उदयपुर (कासं)। शहर के शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में स्थित जैन मंदिर से चोर चांदी के छत्र एवं नकदी चुरा ले गए। पुलिस की जानकारी अनुसार पीडित महावीर प्रसाद पुत्र नेमीचंद जैन निवासी नेमीनाथ जैन कॉलोनी सेक्टर 3 ने प्रकरण दर्ज करवाया कि 26 सितम्बर को रात में आए चोर ने मीनाथ कॉलोनी स्थित शंतिनाथ मंदिर से 2 चांदी के छत्र सहित 4 छत्र व दानपेटी से नकदी सहित करीब 4 लाख का माल चुरा ले गए। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की है।

शिविर 28 से 30 सितम्बर तक

उदयपुर (निसं)। भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के दिशा-निर्देशानुसार जिले में 28 से 30 सितंबर तक ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के साथ आमजन की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जाएगा।

गवरी नृत्य को पाखंड बताने वाले के खिलाफ प्रदर्शन

■ उदयपुर कलेक्ट्री पर लोगों ने धरना दिया, औरत का स्वरूप रखने पर सवाल उठाए थे जिस कारण उस युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई

उदयपुर (कासं)। उदयपुर में आदिवासियों के गवरी नृत्य को लेकर एक युवक की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सोमवार को लोगों ने कलेक्ट्री पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना था कि युवक ने अपनी पोस्ट में गवरी नृत्य को पाखंड करार देते हुए कई सवाल उठाए थे। गवरी आदिवासी समाज की ऐतिहासिक परंपरा है। जिसे उन्होंने आज तक सहेजकर रखा हुआ है।

प्रदर्शनकारियों के अनुसार सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणी से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। समाज के लोगों ने जिला प्रशासन से मामले की जांच कर संबंधित युवक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग उठाई। ताकि आगे कोई तरह की टिप्पणी नहीं करे। जानकारी अनुसार करीब 3 दिन पहले एक युवक ने गवरी नृत्य करने वाले व्यक्ति से बातचीत का वीडियो खुद के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। युवक ने गवरी के पात्रों पर सवाल उठाते कहा था कि गवरी नृत्य करने वाले मर्दों को पेरों में घूंघरू, कानों में कुंडल और लिपिस्टि लगाने के लिए किसने बोला। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो पाखंडवाद है।

सोशल मीडिया परयुवक का नाम हेप्पीसिंह बताया गया है लेकिन वो मूल रूप से किस शहर का निवासी है यह कही उल्लेख नही है।उसने गवरी में माता शिव और पार्वती के स्वरूप पर भी सवाल उठाए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद आदिवासी समाज में विरोध बढ़ गया और युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी। हालांकि दूसरे दिन ही आरोपी युवक ने दूसरा वीडियो जारी कर माफी मांग ली।

रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की जानकारी दी

उदयपुर (कासं)। घुटना प्रत्यारोपण में आधुनिक रोबोटिक तकनीक के उपयोग एवं मरीजों को मिलने वाले लाभों को लेकर उदयपुर में विशेष सीएमई (हेल्थ शिविर)का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अहमदाबाद पारेख्स हॉस्पिटल के वरिष्ठ रोबोटिक सर्जन डॉ. विनय पाराशर ने घुटना प्रत्यारोपण में अपनाई जा रही नवीन तकनीकों के बारे में जानकारी दी। सीएमई में कई वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद थे। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. बलदीप शर्मा, वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट, उदयपुर द्वारा किया गया। डॉ. विनय पाराशर ने रोबोटिक तकनीक से होने वाले घुटना प्रत्यारोपण की प्रक्रिया एवं इसमें उपयोग होने वाली आधुनिक तकनीक के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि आधुनिक रोबोटिक तकनीक का उद्देश्य शल्य चिकित्सा में अधिक सटीकता प्राप्त करना और मरीज के उपचार एवं पुनर्वास की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। उन्होंने लंबे समय से घुटने के दर्द से परेशान मरीजों के लिए घुटना प्रत्यारोपण के आधुनिक विकल्पों पर भी चर्चा की।सीएमई में उदयपुर के अनेक वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट उपस्थित रहे।

सार-समाचार

पराया की भागल में जल्द बीएसएनएल का 4जी नेटवर्क दौड़ेगा

उदयपुर (कासं)। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लंबे समय से नेटवर्क समस्या से जूझ रहे पराया की भागल के ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है। बीएसएनएल के 4जी सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत गांव में मोबाइल टावर स्थापित किया जाएगा। पराया की भागल के साथ बड़गांव उपखंड के पीपड़, कुंडल और तुला गांवों को भी परियोजना के तहत चिन्हित किया गया है। पराया की भागल में टावर लगाने के लिए बीएसएनएल द्वारा भूमि की मांग की गई थी, लेकिन बिलानाम भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रक्रिया अटकी हुई थी।मामले में जांच के बाद ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में से 2,000 वर्ग फीट भूमि का नि:शुल्क पट्टा तत्काल जारी किया। विकसित भारत सेवा सेतु अभियान के तहत बड़गांव में आयोजित शिविर में उपखंड अधिकारी मनसुख डामोर, तहसीलदार हितेश त्रिवेदी एवं विकास अधिकारी अजीत मीणा की मौजूदगी में पट्टा बीएसएनएल प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर ग्राम विकास अधिकारी रामा ने मौके पर ही पट्टा जारी करने की कार्रवाई पूरी की। अब बीएसएनएल द्वारा शीघ्र ही टावर लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। टावर शुरू होने के बाद क्षेत्र की करीब 2 हजार की आबादी को बेहतर 4जी नेटवर्क सुविधा मिलने की उम्मीद है।

''पैसिफिक स्कूल ऑफ लॉ'' में ई-फ्रेशर्स पार्टी आयोजित

उदयपुर (कासं)। पैसिफिक स्कूल ऑफ लॉ में नवांगतुक विद्यार्थियों के स्वागत के लिए फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम डिस्को रही, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों के परिचय एवं रैम्प वॉक से हुई। इसके बाद टैलेंट राउंड एवं प्रश्नोत्तर राउंड का आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास एवं रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत डांस परफॉर्मेंस दी। फ्रेशर्स पार्टी में राहुल सिंह चौहान को मिस्टर फ्रेशर्स तथा इशिता जैन को मिस फ्रेशस चुना। वहीं रिशियांशु सिंह व माहिका सोनी को रनर अप का खिताब दिया। उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के लिए हिमानी, लिपिका एवं धर्मवीर को बेस्ट परमोरमेंस के सम्मान दिया। वहीं आकर्षक परिधान के लिए सुमित पालीवाल, आयुर्ाी भारद्वाज एवं मोक्षा शर्मा को बेस्ट ड्रेस का सम्मान दिया। कार्यक्रम के अंत में डीन-इन-चार्ज डॉ. अनुराग मेहता ने सभी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पैसिफिक स्कूल ऑफ लॉ के सभी संकाय सदस्य उपस्थित रहे।

3 लाख 55 हज़ार लीटर से अधिक वॉश नष्ट, 416 गिरफ़्तार हुए

उदयपुर (कासं)। प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोकथाम के लिए चल रहे अभियान के तहत कार्यवाही जारी है। प्रदेश में वॉश, हथकडी मदिरा सहित अन्य राज्य की मदिरा पर भी कार्रवाई की जा रही है अब तक 3 लाख 55 हजार 711 लीटर वॉश नष्ट किया है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत 27 सितंबर तक विभिन्न कार्रवाई के तहत 1064 अभियोग दर्ज किए गए है। प्रदेश में देशी मदिरा 8 लाख 17 हजार 785 रूपए लागत की 2988 लीटर, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एक करोड 4 लाख 96 हजार 520 रूपए की 10552 लीटर, बीयर 3 लाख एक हजार 501 रूपए की 137०लीटर, हथकडी शराब 8937 लीटर एवं स्प्रिट 350 लीटर जब्त किया। इसी क्रम में वॉश 3 लाख 55 हजार 711 लीटर नष्ट किया गया। प्रदेश में अभियान के तहत एक बड़ा वाहन, 13 चार पहिया वाहन, 22 दुपहिया वाहन सहित 36 वाहन जब्त है साथ ही अवैध मदिरा से संबंधित 416 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार प्रदेश के समस्त जिलों में भी विषेष निरोधात्मक अभियान के तहत नाकाबंदी, दबिश व सघन गश्त की जा रही है। समस्त अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, आबकारी उपायुक्त, जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक एवं आबकारी निरोधक दल द्वारा अवैध मदिरा के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्यवाही की जा रही है।

विश्व हृदय दिवस: दिल की धड़कन को समझें, दिल का ख्याल रखें

विश्व हृदय दिवस हर वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हृदय रोग और स्ट्रोक सहित हृदय एवं रक्तवाहिका संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को अपने हृदय के स्वास्थ्य के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है।

दिल की बीमारी—खामोश खतरे को पहचानना जरूरी

हमारा हृदय दिन-रात बिना रुके काम करता है। लेकिन बदलती जीवनशैली, शारीरिक निष्क्रियता, धूम्रपान, अस्वास्थ्यकर खान-पान, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग का खतरा बढ़ा सकते हैं। विश्व हृदय महासंघ के अनुसार, हृदय एवं रक्तवाहिका संबंधी रोग दुनिया में मृत्यु का प्रमुख कारण हैं।

सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हृदय रोग हमेशा स्पष्ट लक्षणों के साथ सामने नहीं आता। कई बार उच्च रक्तचाप या अन्य जोखिम कारक लंबे समय तक बिना किसी खास लक्षण के रह सकते हैं। इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच और जोखिम कारकों की पहचान बेहद महत्वपूर्ण है। 2026 की विश्व हृदय दिवस मुहिम भी लोगों को हृदय रोग के संकेतों को पहचानने और “Don’t Miss a Beat” यानी किसी महत्वपूर्ण धड़कन या चेतावनी संकेत को नजरअंदाज न करने का संदेश देती है।

विश्व हृदय दिवस केवल एक दिन जागरूकता फैलाने का अवसर नहीं, बल्कि पूरे वर्ष अपने और अपने परिवार के हृदय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का संकल्प है। सही खान-पान, नियमित व्यायाम, समय पर स्वास्थ्य जांच और चेतावनी संकेतों की जानकारी-ये छोटे कदम गंभीर हृदय रोगों से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

इन लक्षणों को कभी न करें नजरअंदाज

- सीने में दबाव, जकड़न, भारीपन या दर्द - खासकर बीच या बाईं तरफ।
- दर्द/भारीपन का बाएं हाथ, दोनों हाथों, कंधे, पीठ, गर्दन, जबड़े या ऊपरी पेट तक जाना।
- सांस फूलना या सामान्य काम में अचानक सांस चढ़ना।
- ठंडा पसीना आना, खासकर बिना गर्मी या मेहनत के।
- अचानक कमजोरी, चक्कर या बेहोशी जैसा महसूस होना।
- मतली, उल्टी या अपच जैसा एहसास, विशेषकर साथ में सीने में असहजता हो।
- अचानक बेचैनी या घबराहट।
- असामान्य थकान, खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और मधुमेह वाले लोगों में।

सबसे महत्वपूर्ण

यदि सीने में दबाव/दर्द 5 मिनट से ज्यादा रहे, बार-बार आए, या उसके साथ सांस फूलना, पसीना, चक्कर, उल्टी अथवा हाथ/जबड़े में दर्द हो, तो इसे गैस या सामान्य कमजोरी मानकर इंतजार न करें। तुरंत स्थानीय आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें और अस्पताल जाएं।

हृदय रोग विशेषज्ञ

डॉ. रमेश पटेल — HOD, Senior Consultant, Dept. of Cardiology
डॉ. संजय गाँधी — HOD, Senior Consultant, Dept. of CTVS
डॉ. दिलीप जैन — Senior Consultant, Dept. of Cardiology
डॉ. गौरव कु. मित्तल — Consultant, Dept. of Cardiology
डॉ. रोहिन के. सैनी — Consultant, Dept. of Cardiology
डॉ. शैलेंद्र दीक्षित — Associate Consultant, Dept. of Cardiology

छोटे बदलाव, बड़ा फायदा

अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए जीवनशैली में छोटे लेकिन नियमित बदलाव किए जा सकते हैं:

- रोजाना शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
- फल, सब्जियां, साबुत अनाज और संतुलित आहार को प्राथमिकता दें।
- तंबाकू और धूम्रपान से दूरी बनाएं।
- रक्तचाप, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की समय-समय पर जांच कराएं।
- स्वस्थ वजन बनाए रखने का प्रयास करें।
- पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन पर ध्यान दें।

गीतांजली मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, एकलिंगपुरा चौराहा के पास, उदयपुर (राज.) 0294-2500044

+91 97733 56092
+91 97845 96209

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना | राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) | कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) | भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) | सभी सरकारी, निजी, टीपीए और बीमा योजनाओं के साथ सूचीबद्ध

www.geetanjalihospital.co.in

मैं सचिन को बहुत सम्मान देता हूं और उनके खिलाफ खेल चुका हूं। उनका करियर जहां भी खत्म होगा, उन्हें इस प्रारूप के महानतम बल्लेबाजों में, बल्कि शायद सबसे महान बल्लेबाजों में शामिल होना ही होगा।

- इयान बिशप

वेस्टइंडीज खिलाड़ी, विराट कोहली की प्रशंसा करते हुए।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी

कगिसो रबाडा

दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी प्रारंभिक टीम में तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा को शामिल किया है। हैमस्ट्रिंग चोट से उबर रहे रबाडा की पहले टेस्ट में उपलब्धता का फैसला अगले सप्ताह होने वाले इंट्रा-स्क्वाड मुकाबले के बाद किया जाएगा। रबाडा को विंटर ट्रेनिंग के दौरान हैमस्ट्रिंग चोट लगी थी और वह फिलहाल उससे उबर रहे हैं। लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन और क्वेना मफाका को हैमस्ट्रिंग चोटों से उबरने के कारण टीम में जगह नहीं मिली है।

क्या आप जानते हैं ?... भारत ने1951 एशियाई खेल में 51 पदक जीते थे, जिसमें 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल था।

आरसीए चुनाव : पराक्रम सिंह व डीडी कुमावत ने अध्यक्ष और बृजकिशोर ने सचिव पद से वापस लिया नामांकन

// धनंजय सिंह, आशीष तिवाड़ी, मोहित यादव ने नहीं छोड़ा मैदान //

जाकिर हुसैन

जयपुर, 28 सितंबर। आरसीए चुनाव अपने रोमांच चरण पर पहुंच चुका है। आज राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह ने सोमवार को अपने गुट के साथ नामांकन वापस ले लिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर भी उपाध्यक्ष पद से नाम वापस लिया। पराक्रम सिंह ने कहा मैंने किसी दबाव में नाम वापस नहीं लिया है। पराक्रम आरसीए अध्यक्ष पद के दावेदार थे। उन्होंने चुनाव लड़ने के दौरान 32 वोटों का समर्थन होने का दावा भी किया था।

पराक्रम ने बृजकिशोर उपाध्याय को समर्थन दिया है। वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह (अध्यक्ष पद पर), सांसद घनश्याम तिवाड़ी के बेटे आशीष तिवाड़ी (कोषाध्यक्ष पद पर) और भाजपा विधायक जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव (सचिव और उपाध्यक्ष पद पर) ने अब तक नामांकन वापस नहीं लिया है। ऐसे में आरसीए का चुनाव अब राजनीतिक रस्साकशी और बदलते समर्थन के बीच दिलचस्प होता जा रहा है।

अध्यक्ष से लेकर संयुक्त सचिव पद तक नाम वापस

आरसीए चुनाव में पराक्रम सिंह के गुट के कार्यकारी सदस्य पद के लिए मैदान में उतरे धर्मवीर शेखावत ने अभी अपना नाम वापस नहीं लिया है। ऐसे में एक तरफ जहां कुछ उम्मीदवारों के हटने से चुनावी समीकरण बदल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ दावेदार अब भी मुकाबले में बने हुए हैं।

मंत्रियों व नेताओं के बेटों पर टिकी नजरें

आरसीए चुनाव में अब सबसे ज्यादा चर्चा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह, सांसद घनश्याम तिवाड़ी के बेटे आशीष तिवाड़ी और भाजपा विधायक जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव को लेकर है। उन्होंने अब तक अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। आरसीए में दिसंबर 2022 में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत निर्विरोध अध्यक्ष बने थे। इसके बाद फरवरी 2024 में इस्तीफा दिया था।

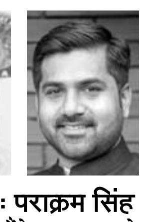

अध्यक्ष बनना चाहता था : पराक्रम सिंह

पराक्रम सिंह ने कहा जब मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तब मेरे पास 32 वोटों का समर्थन था। संख्या बल के लिहाज से मेरा गुट मजबूत स्थिति में था। मैं खुद आरसीए का अध्यक्ष बनना चाहता था। मेरे साथियों ने भी अलग-अलग पदों के लिए नामांकन दाखिल किए थे। सरकार के स्तर पर अलग फैसला हुआ। सरकार ने बृजकिशोर उपाध्याय को अध्यक्ष बनाने और उनके साथियों को छह सदस्यीय कार्यकारिणी में जगह देने का निर्णय लिया। इसके बाद मैंने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए अपने गुट के साथ नामांकन वापस लेने का निर्णय किया।

पराक्रम सिंह ने कहा मेरे संस्कार मुझे पार्टी के खिलाफ जाने का फैसला करने की अनुमति नहीं देते इसलिए मैंने बृजकिशोर उपाध्याय के नेतृत्व में नाम वापस लेने का निर्णय किया। मुझे उम्मीद ही नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि बृजकिशोर उपाध्याय आरसीए के लिए अच्छा काम करेंगे। हमने आज उस फैसले का सम्मान करते हुए अपना फॉर्म वापस ले लिया है। जिस दिन मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, उससे पहले पार्टी का फैसला हो गया था। हमने उसी दिन उस फैसले को मान लिया था। मैंने प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया था। ऐसा हर चुनाव में होता ही है कि एक डमी कैंडिडेट ज़रूर चुना जाता है। भगवान न करे, अगर हमारे मेन कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो ऐसा न हो कि हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां न रहे। जैसे मैंने प्रेसिडेंट पर एक डमी चुना था। बृज किशोर ने सचिव पर एक डमी चुना था। हम सबने ऐसा फॉर्म बनाया था। हमारी पार्टी में, फैसला मेरिट के आधार पर होता है। कोई पिक एंड चूज़ नहीं होता। कोई यह नहीं देखता कि वह किस परिवार से है या नहीं। और पार्टी ने जो भी पैनल बनाया है, मेरा मानना है कि वह सेल्फ-सर्विंग पैनल है। मनोज शर्मा हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। यह हमारा ओरिजिनल छह लोगों का पैनल था।मेरा मानना है कि बृज किशोर जिस दिन से मैंने क्रिकेट में पहला कदम रखा, उस दिन से, उन्होंने एक भाई की तरह हर कदम पर मेरा साथ दिया है। मेरा मानना है कि आज बृज किशोर हेड बन रहे हैं तो एक तरह से मेरे भाई लीडर बन रहे हैं।

इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट

इलेक्शन ऑफिसर (पी.एस. हाडा) (रिटायर्ड. आरएचजेएस) असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर, ए.के. पांडे, (रिटायर्ड. आईएएस), ने बताया इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट :

प्रेसिडेंट कैंडिडेट के नाम : धनंजय सिंह खिमसर, बृज किशोर उपाध्याय

वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के नाम : मोहित यादव, रतन सिंह शेखावत

सेक्रेटरी कैंडिडेट के नाम : मोहित यादव, पिंकेश कुमार जैन

जॉइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट के नाम : विनोद सहारण, राजेश सारस्वत

ट्रेजरर कैंडिडेट के नाम : आशीष तिवारी, विष्णु प्रकाश अग्रवाल

एग्जीक्यूटिव मेंबर कैंडिडेट के नाम : अरिष्ठ सिंघवी, धर्मवीर सिंह शेखावत

आरसीए एजीएम व चुनाव आज

चुनाव अधिकारी ए.के. पांडे ने बताया, आरसीए चुनाव में 18 नामांकन वापस, अब 12 उम्मीदवार मैदान में, सभी 6 पदों पर आमने-सामने मुकाबला, कुल 30 नामांकन प्राप्त हुए थे, आरसीए के 6 पदों पर दो-दो उम्मीदवार आमने-सामने, मंगलवार सुबह 11 बजे एजीएम होगी, फिर होंगे चुनाव, मंगलवार सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक होगा मतदान, मतदान के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे के बाद मतगणना और परिणाम घोषित होगा।

आरसीए चुनाव अधिकारी भ्रष्ट : दीनदयाल

जयपुर। आरसीए एडहॉक कमेटी के पूर्व कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने अध्यक्ष पद से नामांकन पत्र वापस ले लिया है। कुमावत ने कहा- चुनाव अधिकारी पूरी तरह से गड़बड़ी कर रहे हैं। जिन जिलों को एनुअल जनरल बॉडी (एजीएम) की मीटिंग ने सस्पेंड कर दिया। उन्हें वोटिंग राइट दिया गया है, जो पूरी तरह नियमों के विपरीत है। इस मामले को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लडूंगा। इस चुनाव को रद्द करवा कर ही दम लूंगा, क्योंकि यह चुनाव नियमों के विपरीत लोकतंत्र के खिलाफ हैं।

जिला क्रिकेट संघ की याचिकाओं पर सुनवाई से इंकार

जयपुर, 28 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए चुनाव में तीन जिलों को मताधिकार दिए जाने सहित दो मुद्दों पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इन याचिकाओं की सुनवाई अब दूसरी एकलपीठ करेगी। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ के डीडी कुमावत व दौसा जिला क्रिकेट संघ की याचिकाओं पर दिए। डीडी कुमावत की ओर से अधिवक्ता सुनील समदडिया ने अदालत को बताया कि आरसीए की एजीएम की बैठक में खैरथल-तिजारा, डीडवाना-कुचामन और बालोतरा जिलों की कार्यकारिणी को सस्पेंड कर दिया था। इसके बावजूद इन्हें आरसीए चुनाव में मताधिकार दिया गया है। इसलिए इनके मताधिकार पर रोक लगाई जाए। वहीं दौसा जिला क्रिकेट संघ की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने कहा कि संघ के सचिव प्रदीप नागर को वोट डालने का अधिकार दिया जाए। दोनों याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार करते हुए अदालत ने इनकी सुनवाई के लिए दूसरी एकलपीठ गठित करने को कहा है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की दखल के बाद अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव मंगलवार को होने जा रहे हैं।

जयपुर में रचेगा इतिहास, ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन

जयपुर, 28 सितंबर। राजस्थान बैडमिंटन संघ व आयोजन सचिव के.के. शर्मा ने बताया कि गुलाबीनगर में 1 से 9 अक्टूबर तक होने वाली योनेक्स सनराईज ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में इतिहास बनेगा। यह पहला मौका जब टूर्नामेंट में महिलाएं ही सभी मैचों में अम्पायरिंग करेगी। अब तक हुये टूर्नामेंटो में पुरूष और महिलाएं मिलकर अम्पायरिंग की भूमिका निभाते रहे है। भारतीय बैडमिंटन संघ ने टूर्नामेंट की मेजबानी के साथ महिला अम्पायरों की सेमीनार की जिम्मेदारी भी राजस्थान बैडमिंटन संघ को सौंपी है। यह पहला मौका है जब सेमीनार में शामिल होने आई महिलाएं टूर्नामेंट में अम्पायरिंग भी करेगी। तीन दिवसीय सेमीनार में शामिल होने के लिए देषभर से 45 महिलाएं आई है। हमें 46 महिलाओं के सेमीनार में भागीदारी करने की सूचना मिली थी। लेकिन पष्चिम बंगाल से एक प्रतिनिधी ने अपना नाम वापस ले लिया। राजस्थान से नीतु रानी सुथार, चंद्रकला रिया और वंषिका सातू भी सेमीनार में हिस्सा ले रही है। सेमीनार के बाद ग्रेड-2 के थ्योरीकल एवं प्रैक्टिकल परीक्षा भी होगी। प्रतियोगिता के दौरान अंडर-15 व अंडर-17 में बालक-बालिकाओं के मुकाबले एकल, युगल व मिश्रित युगल में मुकाबले होगे। मंगलवार से खिलाड़ियों का आना शुरू हो जाएगा।

// एशियाई खेल //

भाला फेंक में यशवीर को रजत, रोहित को कांस्य, पथिरागे ने जीता स्वर्ण

नागोया, 28 सितंबर। एशियन खेल-2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत ने दो पदक अपने नाम किए। यशवीर सिंह ने रजत और रोहित यादव ने कांस्य पदक जीता। श्रीलंका के डायमंड लीग चैंपियन रुमेश पथिरागे ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की गैरमौजूदगी में यशवीर और रोहित ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर जगह बनाई। यशवीर ने अपने अभियान की शुरुआत 83.56 मीटर की थ्रो से की, लेकिन पदक पक्का करने के लिए उन्हें अंतिम प्रयास तक इंतजार करना पड़ा। अपने छठे और आखिरी प्रयास में उन्होंने 85.72 मीटर भाला फेंककर रजत पदक पक्का किया। यह उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा और इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी क्वालीफाई कर लिया। रोहित यादव की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उनका पहला प्रयास केवल 77.25 मीटर का रहा। हालांकि तीसरे प्रयास में उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए 84.35 मीटर की दूरी तय की और कांस्य पदक अपने नाम किया। श्रीलंका के रुमेश पथिरागे ने बारिश के बीच शानदार प्रदर्शन किया। इस साल दो बार 90 मीटर का आंकड़ा पार कर चुके पाथिरागे ने चौथे प्रयास में 88.33 मीटर की दूरी तय कर बढ़त बनाई। इसके बाद अपने अंतिम प्रयास में उन्होंने 88.55 मीटर का थ्रो करते हुए स्वर्ण पदक पक्का कर लिया। पाकिस्तान के अरशद नदीम 80.29 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ चौथे स्थान पर रहे। जापान के युता साकियामा 78.74 मीटर के साथ पांचवें स्थान पर रहे।

एशियन खेल में पारुल चौधरी को मिला दूसरा पदक, 5000 मीटर दौड़ में जीता कांस्य

नागोया, 28 सितंबर। भारत की लंबी दूरी की धाविका पारुल चौधरी ने सोमवार को एशियन खेल-2026 में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीत लिया। पारुल ने फाइनल में 15 मिनट 14.61 सेकंड का समय निकालकर पोडियम पर जगह बनाई। यह मौजूदा एशियन खेल में उनका दूसरा पदक है। पारुल के लगातार दो एशियन खेल में पदक जीतने से भारत की एथलेटिक्स टीम के अभियान को भी मजबूती मिली है। उन्होंने एक ही प्रतियोगिता में अलग-अलग लंबी दूरी की स्पर्धाओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है।

मुक्केबाज कपिल पोखरिया सेमीफाइनल में, भारत का एक और पदक पक्का

आइची-नागोया, 28 सितंबर। भारतीय मुक्केबाज कपिल पोखरिया ने एशियन खेल-2026 में सोमवार को पुरुषों के 90 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया के किम गिचाए को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ कपिल ने भारत के लिए एक और पदक पक्का कर दिया। कद का फायदा मिलने के कारण कपिल ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। पहले राउंड में उनके बाएं हाथ के हुक लगातार निशाने पर लगे और उन्होंने पांचों जजों का समर्थन हासिल करते हुए 5-0 से राउंड अपने नाम किया।

भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर पुरुष स्क्वैश के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

आइची-नागोया, 28 सितंबर। गत चैंपियन भारत ने एशियन खेल 2026 में सोमवार को पुरुष स्क्वैश टीम स्पर्धा के ग्रुप चरण में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ भारत ने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत के लिए वेलावन सेंथिलकुमार ने जीत की शुरुआत की। उन्होंने दक्षिण कोरिया के ना जूयंग को सीधे तीन गेम में 11-6, 11-4, 11-7 से हराया। वेलावन ने पहले गेम से ही मुकाबले पर नियंत्रण बनाए रखा और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद अभय सिंह ने यू जियोंगमिन को 11-4, 11-7, 11-1 से हराकर भारत की बढ़त 2-0 कर दी। अभय ने पहले गेम में आसानी से जीत दर्ज की और इसके बाद लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। मुकाबला भारत के पक्ष में तय होने के बाद वीर चोत्रानी ने दक्षिण कोरिया के ओह सोजिन को 11-6, 11-4, 11-2 से हराकर भारत को 3-0 की शानदार जीत दिला दी।

भारतीय महिला स्क्वैश टीम की लगातार दूसरी जीत, जापान को 2-1 से हराया : भारतीय महिला स्क्वैश टीम ने एशियन गेम्स-2026 में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सोमवार को जापान को 2-1 से हरा दिया। चीन के खिलाफ शुरुआती मुकाबले में 2-1 की जीत के बाद यह भारत की लगातार दूसरी जीत है। भारत को शुरुआती बढ़त जोशना चिनप्पा ने दिलाई। उन्होंने जापान की एरिसा सानो को 11-1, 11-8 से हराकर मुकाबले में भारत को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद अनाहत सिंह का सामना सातोमी वातानाबे से हुआ। वातानाबे ने पहला गेम 11-8 से जीतकर अच्छी शुरुआत की, लेकिन अनाहत ने वापसी करते हुए अगले दो गेम 11-8 और 11-7 से जीत लिए। हालांकि जापानी खिलाड़ी ने चौथा गेम 11-8 से अपने नाम कर मुकाबले को निर्णायक पांचवें गेम तक पहुंचा दिया। निर्णायक गेम में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन वातानाबे ने 11-9 से जीत दर्ज करते हुए मैच 11-8, 8-11, 7-11, 11-8, 11-9 से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही जापान ने मुकाबले में 1-1 की बराबरी कर ली। इसके बाद निर्णायक मुकाबले में तन्वी खन्ना ने जिम्मेदारी संभाली।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बांग्लादेश को 10-0 से रौंदा, सेमीफाइनल में पाकिस्तान से होगी भिड़ंत

काकामिगाहारा, 28 सितंबर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स-2026 में अपने पूल ए अभियान का शानदार अंदाज में अंत करते हुए बांग्लादेश को 10-0 से हरा दिया। लगातार पांचवीं जीत के साथ भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल किया और अब 1 अक्टूबर को सेमीफाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया और दक्षिण कोरिया आमने-सामने होंगे।

भारी बारिश और पानी से भरे मैदान के बावजूद भारतीय टीम ने पूरे मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने शानदार हैट्रिक लगाई, जबकि शिलानंद लाकड़ा ने दो गोल किए। मैच की शुरुआत बारिश के कारण 30 मिनट की देरी से हुई। इसके बावजूद भारत ने तीसरे मिनट में ही बढ़त बना ली। अभिषेक ने शानदार रिवर्स हिट के जरिए गेंद को बांग्लादेशी गोलकीपर के पार पहुंचाकर भारत को 1-0 से आगे कर दिया।

दूसरे क्वार्टर में भारत को 22वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक से गोल में बदलकर भारत की बढ़त 2-0 कर दी। इसके बाद 27वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने जोरदार ड्रैग-फ्लिक के जरिए गोल कर स्कोर 3-0 कर दिया। तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में सुखजीत सिंह ने गोल कर भारत की बढ़त 4-0 कर दी।

40वें मिनट में हरमनप्रीत ने एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 5-0 किया। शिलानंद लाकड़ा ने 44वें और 45वें मिनट में लगातार दो गोल दागकर भारत की बढ़त 7-0 कर दी।

45वें मिनट में हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर पर अपना तीसरा गोल किया और हैट्रिक पूरी करते हुए भारत को 8-0 की बढ़त दिला दी। संजय ने पेनल्टी कॉर्नर पर शानदार गोल कर भारत को 9-0 से आगे किया, जबकि 60वें मिनट में मनदीप सिंह ने रिबाउंड पर गोल कर भारत की जीत 10-0 कर दी। इस जीत के साथ भारत ने पूल ए में इंडोनेशिया, श्रीलंका, जापान, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश को हराया। अब टीम दो दिन के विश्राम के बाद 1 अक्टूबर को सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी।

टीम जयपुर ने आर्मी कमांडर्स कप जीता

जयपुर, 28 सितंबर। वार्षिक सितम्बर जयपुर पोलो सीज़न 2026 के तहत रविवार शाम को कैवेलरी ग्राउंड पर आर्मी कमांडर्स कप (06 गोल्स) का फाइनल मुकाबला खेला गया। टीम जयपुर और टीम वी पोलो के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में टीम जयपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11-5 के स्कोर से जीत दर्ज की और आर्मी कमांडर्स कप का खिताब अपने नाम किया। टीम जयपुर के लिए पद्मनाभ सिंह ने अकेले 8 गोल कर टीम को जीत दिलाई। टीम से मार्टिन कार्लोस डोनोवन ने 2 गोल और विश्वराज सिंह ने 1 गोल किया। टीम से अक्षय मलिक भी खेले। वहीं, टीम वी पोलो की ओर से विशाल सिंह राठौड़ ने 3 गोल और गोंज़ालो मिगुएल यांजों ने 2 गोल किया। टीम में निमित मेहता और मुकेश सिंह भी शामिल रहे।

जयपुर की हिमानी पूनिया ने केपटाउन सीनियर्स इंटरनेशनल में जीता स्वर्ण और रजत

जयपुर, 28 सितंबर। जयपुर की दो बार की राष्ट्रीय चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी हिमानी पूनिया ने घुटने की सर्जरी के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित केपटाउन सीनियर्स इंटरनेशनल 2026 में स्वर्ण और रजत पदक जीते। 23 से 27 सितंबर तक केपटाउन के केनिलवर्थ स्थित जॉन टायर्स हॉल में आयोजित इस प्रतियोगिता में हिमानी ने महिला एकल 40 वर्ग में स्वर्ण पदक और महिला युगल 45 वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड सीनियर सर्किट का हिस्सा थी। महिला युगल में हिमानी ने रीयूनियन आइलैंड की क्लेन वर्जिनी के साथ जोड़ी में रजत पदक हासिल किया। वहीं, महिला एकल में स्वर्ण पदक जीतना उनके लिए विशेष उपलब्धि रहा, क्योंकि यह उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला एकल में पहला स्वर्ण पदक है।

आरयूएफसी ने कैस्टेलानो का स्वागत किया

जयपुर, 28 सितंबर। राजस्थान यूनाइटेड एफसी को यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि स्पेनिश डिफेंडर एड्री कैस्टेलानो 2026-27 सीज़न से पहले डेजर्ट वॉरियर्स में शामिल हो गए हैं। स्पेन के पेशेवर फुटबॉल का अनुभव और प्रतिष्ठित रियल मैड्रिड अकादमी से शुरू हुई फुटबॉल यात्रा अपने साथ लेकर कैस्टेलानो राजस्थान पहुंचे हैं। जहाँ वे एक नई चुनौती को स्वीकार करने और भारतीय फुटबॉल में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं।

मुरली श्रीशंकर को लंबी कूद में रजत

आइची-नागोया, 28 सितंबर। भारत के स्टार लंबी कूद खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने सोमवार को एशियन खेल-2026 में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया। श्रीशंकर ने फाइनल में 8.07 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई। यह एशियन खेल में उनका लगातार दूसरा रजत पदक है। इससे पहले उन्होंने हांगझोऊ 2023 में भी रजत पदक जीता था। फाइनल में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। शीर्ष चार खिलाड़ियों के बीच सिर्फ 12 सेंटीमीटर का अंतर रहा। श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर अनवारोव को महज एक सेंटीमीटर से पीछे छोड़ा और रजत पदक पक्का किया।

गुलवीर सिंह ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ 1500 मीटर दौड़ में जीता रजत : भारतीय धावक गुलवीर सिंह ने एशियन खेल-2026 में पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर ने फाइनल में 3:36.72 मिनट का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया।

विथ्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ में जीता कांस्य, नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया : भारतीय एथलीट विथ्या रामराज ने एशियन खेल-2026 में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। विथ्या ने फाइनल में 54.75 सेकंड का समय निकालकर यह उपलब्धि हासिल की। विथ्या ने अपना ही साझा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर किया। इससे पहले 55.42 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड विथ्या रामराज और महान धाविका पीटी उषा के नाम संयुक्त रूप से था। विथ्या ने 2023 हांगझोऊ एशियन खेल में इस समय की बराबरी की थी। अब नागोया में 54.75 सेकंड का समय निकालकर उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

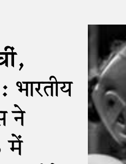

प्रिया घांघस सेमीफाइनल में पहुंचीं, पदक किया पक्का : भारतीय मुक्केबाज प्रिया घांघस ने एशियन गेम्स-2026 में महिलाओं के 60 किग्रा वर्ग के क्वार्टरफाइनल में ताजिकिस्तान की मिजगोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली और भारत के लिए एक और पदक पक्का कर दिया। मुकाबले की शुरुआत दोनों मुक्केबाजों के बीच कड़ी टक्कर के साथ हुई। पहले राउंड में समादोवा ने जजों के 3-2 के फैसले से बढ़त बनाई। पांच में से तीन जजों ने राउंड समादोवा के पक्ष में 10-9 दिया, जबकि दो जजों ने प्रिया को 10-9 से विजेता माना।

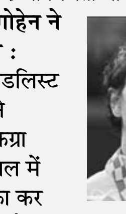

लवलीना बोरगोहेन ने पदक किया पक्का : भारतीय ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं की 75 किग्रा कैटेगरी में सेमीफाइनल में पहुंचकर मेडल पक्का कर लिया। उन्होंने दक्षिण कोरिया की 2010 एशियाई खेलों की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सियोंग सुयोन को सर्वसम्मति से 5-0 से हराया। लवलीना ने जजों के स्कोरकार्ड पर पहला राउंड 10-9 से जीता और अगले दो राउंड 5-0 से जीतकर 30-27 से जीत हासिल की।

हमारी सरकार घोषणाएं ही नहीं करती, उसे समय से धरातल पर भी उतारती है- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने बयाना में भरतपुर संभाग के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया

जयपुर, 28 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार केवल घोषणाएं ही नहीं करती, बल्कि उन्हें समयबद्ध रुप से धरातल पर उतारने का कार्य करती है। इसी क्रम में भरतपुर संभाग को विकास की नई गति देते हुए करीब 453 करोड़ रुपये के 65 बडे विकास कार्यों का लोकार्पण और 540 करोड़ रुपये के 184 नवीन विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में आधुनिक आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बयाना व ब्रज नगर में आधुनिक स्टेडियम, थानाडांग, सूपा व महलपुर चूरा में 33 केवी सब-स्टेशन के निर्माण की घोषणा की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को भरतपुर के बयाना के बिड़्यारी में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। इस दौरान विधायक ऋतु बनावत ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।

मुख्यमंत्री सोमवार को भरतपुर जिले के बयाना के बिड़्यारी में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह का संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भरतपुर को 382 करोड़ रुपये से अधिक के 130 कार्यों, डीग को 358 करोड़ रुपये से अधिक के 24 कार्यों, करौली को 136 करोड़ रुपये से अधिक के 43 कार्यों, सवाई माधोपुर को 74 करोड़ रुपये से अधिक के 46 कार्यों और धौलपुर को 42 करोड़ रुपये से अधिक के 6 विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास की सौगात मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में 273 करोड़ रुपये के 14 बड़े कार्यों का लोकार्पण हुआ है तथा चुली व अनियाला में नए 33 केवी सब–स्टेशनों का भी निर्माण किया जाएगा।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने बयाना और ब्रज नगर में आधुनिक स्टेडियम के निर्माण और थानाडांग, सूपा एवं महलपुर चूरा में 33 केवी सब–स्टेशनों के निर्माण की घोषणा की।

आईआईटी आत्महत्या के मामले में पिता ने आज़ाद मैदान पर धरना दिया

मुंबई, 28 सितंबर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में उनके पिता रवीन्द्र वाकोडे ने सोमवार को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। परिवार ने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और साहिल को न्याय दिलाने की मांग की है। परिवार का आरोप है कि साहिल को संस्थान में कथित तौर पर जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था।

रवीन्द्र वाकोडे ने कहा कि वे अपने बेटे को न्याय मिलने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। रवीन्द्र वाकोड़े के वकील निखिल कांबले ने बताया कि वाकोडे परिवार आजाद मैदान में भूख हड़ताल कर रहा है और एफआईआर में नामजद लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।

जस्टिस विक्रम नाथ भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे

वे अगले साल फरवरी में पद संभालेंगे, जब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत रिटायर हो जाएंगे

नई दिल्ली, 28 सितंबर। जस्टिस विक्रम नाथ भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री पूरी करने के चार दशक बाद, जस्टिस नाथ अगले साल फरवरी में देश के अगले सीजेआई की जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि वर्तमान 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत अगले साल फरवरी में रिटायर हो रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक है।

■ सितम्बर 1962 में जन्मे जस्टिस विक्रम नाम 2004 में इलाहाबाद में एडीशनल जज तथा 2006 में परमानेंट जज बने थे। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने से पहले वे गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे।

जस्टिस विक्रम नाथ मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म 24 सितंबर, 1962 में हुआ था। जस्टिस नाथ ने 1983 में साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने 1986 में लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की थी और इसके बाद 1987 में यूपी बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया।

2004 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनने से पहले, जस्टिस विक्रम नाथ ने वहां 17 साल से ज्यादा समय तक प्रैक्टिस की। 2006 में वे परमानेंट जज बने। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने से पहले, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया। 15 अप्रैल 2022 को एक समारोह में बोलते हुए उन्होंने शिया कॉलेज में अपने स्टूडेंट लाइफ के अनुभव शेयर किए थे। उस समय उन्होंने कहा कि कॉलेज ने मेरी सफलता में अभूतपूर्व योगदान दिया। अगर शिया कॉलेज न होता, तो मैं कुछ भी नहीं होता।

एआई की दुविधा अब केवल काल्पनिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उपयोग करना चाहती हैं, जबकि टैक्नॉलजी कंपनियाँ अधिक उन्नत सिस्टम बनाने की होड़ में लगी हैं। वही तकनीक, जो अभूतपूर्व उत्पादकता का वादा करती है, आर्थिक और तकनीकी शक्ति को कुछ बड़ी कंपनियों के हाथों में केन्द्रित भी कर सकती है।

क्या इन सिस्टमों को बनाने वाली कंपनियों पर खुद को नियंत्रित करने के लिए भरोसा किया जा सकता है? जिम्मेदार इनोवेशन के बारे में कॉर्पोरेट आश्वासन स्वतंत्र निगरानी का विकल्प नहीं हो सकते। दूसरी ओर, बहुत ज्यादा सख्त नियम निवेश को हतोत्साहित कर सकते हैं और शोध की गति को धीमा कर सकते हैं।

एआई से जुड़े इस मुद्दे का भारत पर खासा असर पड़ सकता है। देश एक वैश्विक एआई पारवरहाउस के रुप में उभरना चाहता है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि यह तकनीक देश की विकास संबंधी प्राथमिकताओं को पूरा करे। एआई से स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा और सरकारी प्रशासन में सुधार हो सकता है। लेकिन पर्याप्त सुरक्षा उपाय न होने पर नागरिकों का डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, नागरिकों को धोखाधड़ी और भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, जबकि ऑटोमेशन रोजगार को प्रभावित कर सकता है।

भारत को ऐसे नियामक ढाँचे की जरूरत है, जो नागरिकों की सुरक्षा करे, लेकिन इनोवेशन के रास्ते में अनावश्यक रुकावटें न डाले। पारदर्शिता, स्वतंत्र सुरक्षा आकलन, जिम्मेदारी तय करने के स्पष्ट नियम और गंभीर घटनाओं की अनिवार्य रिपोर्टिंग इसके स्पष्ट आधार होने चाहिए। इसका अंतरराष्ट्रीय पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक देश में विकसित किए गए एआई सिस्टम दुनिया भर के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। सुरक्षा, सिक्योरिटी और जवाबदेही के लिए आम सिद्धांत तय करने के लिए सरकारों के बीच सहयोग जरूरी है।

अंततः सवाल यह नहीं है कि एआई को नियंत्रित किया जाना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि रैगुलेशन को तकनीकी बदलाव की गति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रखा जाए। न तो कंपनियों को बिना रोकटोक के पूरी शक्ति देना और न ही जरूरत से ज्यादा सरकारी नियंत्रण कोई स्थायी समाधान है। एआई गवर्नेंस की असली परीक्षा यह होगी कि क्या समाज इनोवेशन के लाभों को बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य को आकार देने की शक्ति उन लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहे, जिन्हें उसके परिणामों के साथ जीना होगा।

मेक इन इंडिया को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ये उद्योग प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे। लंबी अवधि की परीक्षा यह है कि क्या कंपनियां सब्सिडी पर बहुत अधिक निर्भर हुए बिना अपनी प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और एक्सपोर्ट को बनाए रख सकती हैं।

निवेश के आंकड़ों को भी सावधानी से समझने की जरूरत है। 2014-15 से 2025-26 के बीच कुल 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमैंट - एफ.डी.आई.) यह दिखाता है कि भारत दुनिया के निवेशकों के लिए आकर्षक है, लेकिन सारा एफ.डी.आई. मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नहीं जाता। इसी तरह, पी.एल.आई. से जुड़े निवेश और उत्पादन के आंकड़े औद्योगिक विस्तार को तो दिखाते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि देश के अंदर वास्तव में कितना मूल्य जोड़ा गया है और इस विस्तार का लाभ कितने व्यापक क्षेत्रों तक पहुंचा है।

रोजगार भी एक महत्वपूर्ण पैमाना है। अगर मैन्युफैक्चरिंग को आर्थिक विकास का व्यापक आधार बनना है, तो उसे कहीं अधिक लोगों को रोजगार देना होगा। सैमीकंडक्टर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे ज्यादा पूँजी वाले उद्योगों के साथ-साथ, टैक्स्टाइल गारमैंट, जूते और फूड प्रोसैसिंग जैसे ज्यादा श्रम वाले क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। औद्योगिक सप्लाई चेन की रीढ़ माने जाने वाले छोटे और मध्यम उद्योगों को भी क्रेडिट, टैक्नॉलजी और एक्सपोर्ट मार्केट तक बेहतर पहुँच की ज़रूरत है।

इसलिए भारत की मैन्युफैक्चरिंग की महत्वाकांक्षाओं के लिए फोकस में अब बदलाव की जरूरत है। अगले चरण में केवल ज्यादा सामान बनाने पर ही नहीं, बल्कि उन्हें डिजाइन करने, उनके पुर्जे विकसित करने, टैक्नॉलजी पर अपना नियंत्रण रखने और ग्लोबल स्तर पर मुकाबला करने वाले घरेलू सप्लायर तैयार करने पर जोर होना चाहिए। मजबूत रिसर्च क्षमता, भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल कर्मचारी और ग्लोबल वैल्यू चेन में गहरी भागीदारी बहुत जरूरी है।

मेक इन इंडिया ने एक अहम नींव रखी है। लेकिन इस पहल की असली कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यह नींव ऐसी मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था बनाती है, जो देश में ज्यादा वैल्यू पैदा करे, बड़े स्तर पर रोजगार दे और केवल सरकारी प्रोत्साहनों के भरोसे नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन के दम पर ग्लोबल स्तर पर मुकाबला करे।

चुनाव आयोग तीन माह में तृणमूण के चुनाव चिन्ह पर फैसला करे- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 28 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों धड़ों के लिए चुनाव चिन्ह विवाद को निपटाने के लिए समय-सीमा तय कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बैंच ने सोमवार को कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए चार हफ्ते और उसके बाद फैसला करने के लिए तीन महीने का समय मुकर्रर किया है।

हालांकि, आयोग के वकील ने इस पर फैसले के लिए छह महीने का समय दिए जाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया। इसके साथ ही, कोर्ट ने कहा कि अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो आप हमारे पास आ सकते हैं। इससे पहले 24 सितंबर को सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि निर्वाचन आयोग इस मामले पर फैसला करने में देरी कर रहा है। उन्होंने सुझाव दिया था कि इस मामले पर निर्वाचन आयोग को रोजाना सुनवाई करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के दो विरोधी गुटों के बीच विवाद के चलते पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया गया था।

उत्तराखंड में आठ हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे

अभियान में 38 लोग बचाये गये, अभी 136 ट्रैकर्स विभिन्न स्थानों पर फंसे हैं

देहरादून, 28 सितंबर। उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खराब मौसम के बीच फंसे ट्रेकर्स, पर्वतारोहियों और पोर्टर्स की सुरक्षित निकासी के लिए सोमवार को युद्धस्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आठ हेलीकॉप्टरों की मदद से ऑडेन कोल क्षेत्र के सभी 29 और कालिंदी पास क्षेत्र के नौ ट्रेकर्स समेत, अब तक 38 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। शेष लोगों की निकासी के लिए अभियान जारी है।

■ अधिकारियों के अनुसार, ऑडेन कोल क्षेत्र में फंसे सभी 29 ट्रैकर्स को सोमवार की सुबह हेलीकॉप्टर से निकाला गया। कालिंदी पास क्षेत्र से 9 ट्रैकर्स को हर्षिल हेलीपैड पहुंचाया गया।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 10 ट्रेकिंग दलों के 136 ट्रेकर्स विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए थे। उनकी निकासी के लिए सोमवार सुबह छह बजे से आठ हेलीकॉप्टरों के जरिए अभियान शुरू किया गया। मौसम और हेलीकॉप्टर संचालन की परिस्थितियों के अनुसार रेस्क्यू रणनीति में लगातार बदलाव किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि ऑडेन कोल क्षेत्र में फंसे सभी 29 ट्रेकर्स को सोमवार सुबह ही हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाल लिया गया।

उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य जांच के बाद उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं, कालिंदी पास क्षेत्र से नौ ट्रेकर्स को हर्षिल हेलीपैड पहुंचाया गया, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के बाद सभी की स्थिति सामान्य पाई गई।

चुनाव आयोग के मुद्दे पर खड़गे ने सीडब्लूसी की आज बैठक बुलाई

नई दिल्ली, 28 सितंबर। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर जारी विवाद के बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के साथ पार्टी की आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर गंभीरता से संघर्ष करेगी और बैठक में सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्य अपने सुझाव देंगे। यह मामला केवल किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है और सीडब्ल्यूसी की बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आयोग के कामकाज को लेकर उसके अपने लोगों की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं।

'जीएसटी अधिकारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताया कि सेंट्रल गुड्स एण्ड सर्विसेज़ टैक्स (सीजीएसटी) 2017, में केवल "गुड्स" (चल संपत्तियां या वस्तुओं) को परिभाषित किया गया है और इस कानून में विशेष रूप से "मनी" (नकदी) के विषय में कोई भी नियम या कायदा नहीं बनाया गया है। सिद्धार्थ रांका का कहना यह अधिनियम केवल चल संपत्ति व वस्तुओं और सेवाओं की खरीद- फरोख्त पर टैक्स से संबंधित है। इस नियम में "मनी", यानी नकदी को कहीं परिभाषित भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि गैरकानूनी तरीके से इस नकदी को जब्त करने की वजह से याचिकाकर्ताओं को न केवल ब्याज, बल्कि मुआवजा भी मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961, की धारा 132 में 'तलाशी और अधिग्रहण (ज़ब्ती)' के संबंध में नियम लिखे गये है। उन्होंने बताया कि इस धारा में भी स्पष्ट लिखा है कि नकदी, सोना व आभूषण को 'वस्तु' की तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये एक ही श्रेणी में नहीं आते है। अदालत ने कई हाईकोर्ट के निर्णयों को देखा और यह निष्कर्ष निकाला कि सीजीएसटी कानून की व्याख्या किसी भी दृष्टिकोण से की जाए, चाहे शब्दशः तरीके से, या सुनहरे नियम को लगाते हुए; जिससे नियम को लागू करने में विसंगतियों व असंगतियों को दूर रखा जा सके, या शरारत का नियम लागू करके कानून को पढ़ा जाये, ताकि कानून की भाषा अस्पष्ट न रहे, तब भी अदालत जीएसटी अधिकारियों को किसी भी सूरत में यह अधिकार नहीं दे सकती कि उन्हें छापे के दौरान नकदी जब्त करने का अधिकार है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में पक्षकार जयपुर जोन के जीएसटी विभाग के एडिशनल डायरेक्टर, वरिष्ठ इटेलिजेंस ऑफिसर, उपायुक्त, राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के अन्य अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की जब्त की गई नकदी वापस लौटाने के आदेश दिये।

यहां उल्लेखनीय है कि कई मामलों में नकदी जब्त करने की कार्रवाई 2023 और 2024 में की गई थी और राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष कई अन्य हाईकोर्ट के निर्णय पेश किये गये थे, जिसमें समानांतर मामलों में अदालत में जीएसटी अधिकारियों को न केवल जब्त की गई नकदी लौटाने के आदेश दिये थे, बल्कि मुआवजा व ब्याज भी देने को कहा था। परंतु हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस गुहार पर कोई आदेश नहीं दिये।

कांग्रेस ने सपा के समक्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

श्रेणियों में बांटा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इसका उद्देश्य बातचीत शुरू होने से पहले संभावित उम्मीदवारों और संगठन की ताकत की पहचान करना है, ताकि गठबंधन होने की स्थिति में पार्टी के पास उम्मीदवारों की कमी न हो।

पार्टी ने 150 सीटों को अपनी पहली श्रेणी में रखा है और उम्मीद है कि बातचीत के दौरान वह इन सीटों की मांग करेगी। कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिया है कि वे नहीं चाहते कि सीटों की अंतिम संख्या 100 से कम हो।

कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है। पार्टी खास तौर पर दलित और ब्राह्मण मतदाताओं पर ध्यान दे रही है और अति पिछड़े समुदायों के बीच भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

जहाँ पार्टी का फोकस ब्राह्मण और दलित मतदाताओं पर है, वहीं, वह मुस्लिम नेताओं को भी अपने साथ जोड़ रही है। इस प्रयास में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को प्रमुख भूमिका दी गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद भी शामिल हैं।

अखिलेश यादव ने हाल ही में रायबरेली से पार्टी की पीडीए (पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक) रथ यात्रा शुरू की। रायबरेली लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी करते हैं। यह कदम ऐसे समय में आया है, जब दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे थे। अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से यह कहते रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कायम है।

2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पांच लोकसभा सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को एक सीट मिली थी।

पांच साल बाद, 2024 के चुनाव में तस्वीर काफी बदल गई। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 लोकसभा सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं। दोनों पार्टियों ने मिलकर 43 सीटें जीतीं, जिससे राज्य में इंडिया गठबंधन, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन से आगे रहा। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम ने एनडीटीवी से कहा कि इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा।

जब अखिलेश यादव ने रायबरेली से अपनी रथ यात्रा शुरू की, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रतिक्रिया दी कि उनकी पार्टी मैनपुरी और इटावा से अपना अभियान शुरू कर सकती है। ज्ञातव्य है कि ये दोनों क्षेत्र समाजवादी पार्टी से मजबूती से जुड़े हुए हैं।

इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस जहां से चाहे, अपना अभियान शुरू कर सकती है, लेकिन उसे इटावा और मैनपुरी में वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना अभियान जारी रखेगी और उन्होंने उन बयानों को खारिज किया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आसानी से किनारे किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी के बिना कोई कुछ नहीं"। उन्होंने आगे कहा, "किसी गलतफहमी में मत रहिए, आपने देखा, बंगाल में क्या हुआ।"

समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जवाब में जोर देकर कहा है कि अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क़ ने कहा कि पार्टी ने मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों से लेकर चुनाव में कथित अनियमितताओं तक के मुद्दे "सड़क से लेकर विधानसभा तक" उठाए हैं।

लेकिन उन्होंने कहा कि गठबंधन कब बनेगा और सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसका फैसला अखिलेश यादव करेंगे, जबकि कांग्रेस की ओर से यह फैसला राहुल गांधी करेंगे।

उज्जैन में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस बीच, उज्जैन शहर के काजी खलीलुर रहमान ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और बाजारों में अनावश्यक रूप से न जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मस्जिद से जुड़ा मामला सुलझा लिया गया है। उज्जैन के जिलाधिकारी रौशन कुमार ने भी लोगों से गलत जानकारी पर विश्वास न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित समुदाय के लोग खुद ही धार्मिक स्थल को दूसरी जगह ले जा रहे हैं।

उपराष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किया। देश के सम्मान के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने की उनकी भावना भारत के युवाओं के साहस और संकल्प का प्रतीक है।

भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जैसे मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने, स्थानीय प्रभावशाली लोगों और राज्य व जिला स्तर पर तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा, ताकि महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में विपक्ष को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़े। पार्टी सूत्रों के अनुसार, जमीनी स्तर की तैयारियों में बूथ समितियों को मजबूत करना, सदस्यता अभियान को विस्तार देना, कार्यकर्ताओं का नियमित प्रशिक्षण और राज्य इकाइयों तथा केन्द्रीय प्रभारियों के बीच बेहतर तालमेल शामिल होगा। नया प्रभारी ढांचा, लगातार निगरानी, फीडबैक और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, ताकि केवल तात्कालिक चुनावी अभियानों से आगे बढ़कर, संगठन की मजबूत और स्थाई मौजूदगी बनाई जा सके। कुल मिलाकर, यह बैठक संकेत देती है कि भाजपा अपने नए नेतृत्व के तहत, 2027 के चुनावों को संगठन के आपसी तालमेल और मजबूती की एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देख रही है।

'कोमा में चल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हो गए थे। उन्हें जयपुर रैफर किया गया और यहां उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। इसके चलते वह 90 फीसदी स्थाई निशक्त हो गए और तब से ही कोमा में ही चल रहे हैं। उनका इलाज घर पर ही किया जा रहा है। इसके बावजूद जुलाई, 2025 से उसके पति को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा। जिस कारण पूरा परिवार ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान में जन्मे बाघ शावक का वजन 13 किलो हुआ

गत 18 अप्रेल को जन्मे शावक को नियोनेटल केयर यूनिट में 24 घंटे निगरानी में रखा गया था

जयपुर, 28 सितम्बर। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बाघिन "भक्ति" ने 18 अप्रैल को जिस बाघ शावक को जन्म दिया था, उसकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। शावक वर्तमान में स्वस्थ है और उसका व्यवहार एवं गतिविधियां सामान्य हैं। वन्यजीव चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की टीम उसकी 24 घंटे निगरानी कर रही है। नियोनेटल केयर यूनिट में विशेष देखभाल और "हैंड रियरिंग" के कारण शावक का वजन बढ़कर 13 किलो हो गया है।

उप वन संरक्षक, वन्यजीव चिड़ियाघर डॉ. आशीष व्यास ने बताया कि बाघिन भक्ति को वर्ष 2024 में वन्यजीव एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत पुणे ज़ू से नाहरगढ़ जैविक उद्यान लाया गया था। वहाँ वर्ष 2024 में नागपुर चिड़ियाघर से लाये गए बाघ "गुलाब" को भक्ति के साथ रखा गया था।

■ अधिकारियों के अनुसार, बाघिन भक्ति के असमान्य व्यवहार तथा उसके द्वारा शावक को दूध नहीं पिलाने के कारण शावक की नाज़ुक स्थिति को देखते हुए उसे वन्यजीव चिकित्सालय की नियोनेटल केयर यूनिट में स्थानांतरित किया गया था।

अधिकारियों के अनुसार, बाघिन भक्ति के असामान्य व्यवहार और दूध नहीं पिलाने के कारण शावक की नाजुक स्थिति को देखते हुए, उसे वन्यजीव चिकित्सालय की नियोनेटल केयर यूनिट में स्थानांतरित किया गया था। यहां शावक की 24 घंटे गहन चिकित्सा निगरानी के साथ हैंड रियरिंग की जा रही है।

नियोनेटल केयर यूनिट में रखे जाने के बाद से शावक के वजन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। उसके विभिन्न चिकित्सा परीक्षण भी कराए गए, जिनकी रिपोर्ट सामान्य आई है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान के उपनिदेशक डॉ. अरविंद माथुर ने बताया कि शावक को आवश्यक विटामिन, मिनरल्स और अन्य सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं। विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए उसका टीकाकरण और डिवर्मिंग भी पूरा कराया जा चुका है।

शावक की दैनिक गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल शावक को चिकन और चिकन सूप दिया जा रहा है। नियोनेटल केयर यूनिट में उसके लिए प्राकृतिक वातावरण तैयार किया गया है, ताकि उसे सुरक्षित और अनुकूल माहौल मिल सके। वन्यजीव चिकित्सक और विशेषज्ञ उसके स्वास्थ्य एवं विकास की नियमित निगरानी कर रहे हैं।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 **जयपुर कार्यालयः** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033 **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371 **अजमेर कार्यालयः** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 **जालौर कार्यालय :-** प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्सः 02973-226424, **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908